केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

17 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

मालवा हेराल्ड

सुविचार

जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान ही पहुँचाते हैं, धैर्य रखिए क्योंकि हर चीज़ अपने सही समय पर ही पूरी होती है।

वर्ष : 17 अंक : 14 | उज्जैन, बुधवार 24 जून 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपए

न्यूज ब्रीफ

ईरान ने BRICS देशों को किया आगाह, NATO जैसा सुरक्षा संगठन बनाने का रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली/ जीएनएस। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और एकतरफा कार्रवाइयों से चिंतित ईरान ब्रिक्स को एक मजबूत सुरक्षा आधारित संगठन के रूप में विकसित होते देखना चाहता है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. गादिर नेजामीपुर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सदस्य देशों के सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में यह बात कही। ईरान का मानना है कि ब्रिक्स के जरिए सदस्य देश सामूहिक रूप से उभरते खतरों का मुकाबला कर सकते हैं और एक नई, न्यायपूर्ण एवं बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था की नींव रख सकते हैं। माना जाता है कि ईरान के इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट, एकतरफा हस्तक्षेप और बाहरी दबाव हैं। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स देश अपनी स्वदेशी क्षमताओं और आपसी एकजुटता के बल पर इन असममित खतरों को अवसर में बदलें और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और स्थायी व्यवस्था का निर्माण करें। डॉ. नेजामीपुर ने ब्रिक्स के भविष्य के रोडमैप को आकार देने के लिए चार प्रमुख प्राथमिकताएं रखीं। इस मुद्दे पर भारत, चीन, रूस या यूएई जैसे देशों की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। ब्रिक्स वर्तमान में सुरक्षा सहयोग पर ध्यान देता है, लेकिन यह मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक खतरों जैसे आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े खतरों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर केंद्रित है। ब्रिक्स अभी तक नाटो जैसे औपचारिक सैन्य गठबंधन या सामूहिक रक्षा संधि की दिशा में नहीं बढ़ा है और सदस्य देशों के अलग-अलग हितों के कारण ऐसा बनना मुश्किल भी माना जाता है। भारत भी ब्रिक्स को मुख्य रूप से आर्थिक, विकास और बहुपक्षीय मंच के रूप में देखता है, न कि एक औपचारिक सैन्य या सुरक्षा संगठन के रूप में। ब्रिक्स के तीन स्तंभ हैं, राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग, और जन-जन संपर्क। भारत इनमें से सुरक्षा स्तंभ को गैर-पारंपरिक खतरों तक सीमित रखना चाहता है। इसके बावजूद ईरान की तरफ से मंगलवार की बैठक में रखा गया यह प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि सितंबर, 2026 में जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी इसे दोहराया जाएगा।

सांप, पहाड़ी और धक्का... 4 दिन पहले भी सिया ने की थी केतन को मारने की कोशिश

पुणे/ जीएनएस। केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और ये खुलासा केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि लोहगढ़ किले से धक्का देकर केतन की हत्या किए जाने से चार दिन पहले, उनकी मंगेतर सिया गोयल ने उसी जगह पर उनकी जान लेने की कोशिश की थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया कि कैसे 14 जून को सिया ने केतन को किले से धक्का दिया था। जब केतन एक झाड़ी पकड़कर बचा गया, तो सिया चिल्लाई कि सांप आ रहा है और फिर उसे गले लगा लिया। विशाल अग्रवाल ने कहा कि 14 जून को वे दोनों अकेले किले पर गए और सिया ने केतन को धक्का दे दिया। धक्का लगने के बाद केतन ने एक झाड़ी पकड़ ली और बच गया। राज खुलने के डर सिया चिल्लाई %सांप-सांप%। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे, तो सबके पासपोर्ट तो थे, लेकिन केतन का पासपोर्ट गायब था। ऐसा लगा कि जैसे कहीं गिर गया हो। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं मिला। इसलिए वे वापस लौट आए और लौटने के बाद, तीसरे या चौथे दिन, उसने फिर से उससे झगड़ा किया और कहा कि उन्हें लोहगढ़ किला जाना है। फिर वो 14 जून को लोहगढ़ गई। उस समय वे दोनों अकेले थे। उसने केतन को धक्का दिया। धक्का लगने के बाद केतन पीछे की ओर फिसला और उसका हाथ एक झाड़ी में फंस गया।

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, मध्यप्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले सिकल सेल एनीमिया रोग के नियंत्रण में आगे है प्रदेश

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ जनजातीय समाज के विकास और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण का कार्य वर्ष 2022 से प्रारंभ हुआ है। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। कई पीढ़ियां प्रभावित करने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग नियंत्रण और उपचार की दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी है। जनजातीय नायकों के सम्मान में प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में राजा भभूत सिंह, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती की स्मृति में विभिन्न आयोजन किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के निकट ग्राम अचारपुरा में पांच दिवसीय शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन और जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महोत्सव में जनजातीय कलाकारों द्वारा तैयार शिल्प कृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इन कलाकृतियों को पारंपरिक शैली में आधुनिकता के साथ पेश करने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलाकारों से आत्मीयता के साथ चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय शिल्प का डंका देश-विदेश में बज रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विरासत से विकास के अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे देश में लोक संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रगति के कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु गत सप्ताह मध्यप्रदेश भ्रमण पर रहीं और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती ने गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयाँ प्रदान की। दुनिया ने उनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम को देखा। रानी दुर्गावती ने गौंडवाना क्षेत्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्कालीन मुगल सत्ता के विरुद्ध अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्र गौरव के लिये संघर्ष करते हुए प्राणों की आहूति दे दी। आज हम रानी कमलापति के पराक्रम के क्षेत्र भोपाल में वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य को नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अनेक जनजातीय वीरों की धरती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदिरंग शिल्पकार महोत्सव में जनजातीय कलाकारों ने प्रकृति के माध्यम से हमारे जीवन में उत्सव के रंग भरने का प्रयास किया है। एनआईडी ने जनजातीय परंपरागत कला को नए आयाम पर पहुंचाया है। कला-संस्कृति के माध्यम से कई लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि का सूर्य उदय होगा। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चहुंमुखी विकास कर रहा है।

राष्ट्रीय फलक पर पहचान बना रही जनजातीय कला-जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन के साथ संयुक्त तत्वावधान में मनाये जा रहे इस आदिरंग शिल्पकार महोत्सव में जनजातीय समाज की प्रतिभा को देखने का अवसर मिला है। एनआईडी के समन्वय से मध्यप्रदेश की परंपरागत शिल्प को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। जनजातीय कार्य विभाग के प्रयासों से जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में इस दिशा में बेहतर कार्य किये जा रहे हैं।

लंबे ब्रेक के बाद मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 48 घंटे में पहुंचेगा मुंबई; यूपी-बिहार में कब आएगी बारिश की फुहार

नई दिल्ली/ जीएनएस। तपती और झुलसाती गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अगले 48 घंटों में इसके मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को अपनी आगोश में लेने की पूरी उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण उमस से राहत मिलेगी। मानसून अब तक तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में दस्तक दे चुका है।

एक तरफ जहां मानसून राहत लेकर आ रहा है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन गया है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित कई राज्यों में 28 जून तक भारी से अत्यंत भारी बारिश (20 सेंटीमीटर से अधिक) का अलर्ट जारी किया गया है। मेघालय में बाढ़ जैसे हालात की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

कहीं राहत, कहीं अब भी आफत- मौसम का यह मिजाज देश को दो हिस्सों में बांट रहा है। जहां एक तरफ गोवा, कोंकण और बिहार में भारी बौछारें पड़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके अब भी भीषण %लू% (हीट वेव) की चपेट में रहेंगे। मौसम का यह दोहरा रूप कहीं खुशियां तो कहीं चुनौतियां लेकर आया है।

उम्मीदों की नई बोआई- खरीफ सीजन में अन्नदाताओं ने रच डाला नया कीर्तिमान- धरतीपुत्रों के पसीने और मेहनत ने एक बार फिर देश के खेतों में सुनहरे कल की नींव रख दी है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में चालू खरीफ सीजन के तहत कुल बोआई का रकबा 119.90 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है।

पिछले साल इसी अवधि में यह 117.95 लाख हेक्टेयर था। खेतों की यह हरियाली देश के खाद्य भंडार और किसानों के बुलंद हौसलों की गवाही दे रही है।

लखनऊ अग्निकांड से सरकार ने लिया सबक, पूरे यूपी में होगा कोचिंग सेंटरों का सर्वे

लखनऊ/ जीएनएस। राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और वैधता को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।

पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर बिना पंजीकरण संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पंजीकृत कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था का भी गहन निरीक्षण कराया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग की विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में कोचिंग संस्थानों का व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।

सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि कौन से संस्थान उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं और कौन बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। अवैध पाए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

केरल में मोदी का डीपफेक वीडियो प्रसारित करने वाले पर कार्रवाई की मांग

तिरुअनंतपुरम/ जीएनएस। केरल भाजपा के एक पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने वाले एआइ-जनरेटेड डीपफेक वीडियो के कथित प्रसार पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस वीडियो का उद्देश्य गलत सूचना फैलाना और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना है। केरल भाजपा के राज्य इंटरनेट मीडिया संयोजक अभिजीत राधाकृष्णन नायर ने इस मामले में राज्य पुलिस प्रमुख को विस्तृत जांच की मांग करते हुए शिकायत सौंपी है। शिकायत में कहा गया है कि 'कैप्पाडी अंसारी' नामक फेसबुक अकाउंट से एक ऐसा वीडियो साझा किया गया, जिसे कथित रूप से जी-7 शिखर सम्मेलन के वास्तविक फुटेज में छेड़छाड़ करके तैयार किया गया था।

नायर ने आरोप लगाया कि वीडियो में विश्व नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। इसके साथ ही इसे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने से पहले आपत्तिजनक टिप्पणियां भी जोड़ी गई थीं। उन्होंने इसे राजनीतिक आलोचना की आड़ में किया गया सुनियोजित साइबर हमला बताया।

छात्रों के भविष्य से अधिक राजनीति को अहमियत देती है कांग्रेस, सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज

नई दिल्ली/ जीएनएस। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ÷छात्रों के भविष्य से ज़्यादा राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। पार्टी मुख्यालय में सुधांशु ने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए नीट-यूजी को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में हो रही दिक्कतों की खबरों का जिक्र करते हुए सुधांशु ने कहा, यह चिंता की बात है कि कांग्रेस के लिए लाखों छात्रों के करियर से अधिक राजनीतिक रैलियों और ड्रामेबाजी की अहमियत है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ़ शैक्षणिक मुद्दों को राजनीतिक तमाशा बनाने में है।

सुधांशु ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राहुल बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय नाटकबाज़ी और ध्यान भटकाने वाली चालें चल रहे हैं।

विपक्ष के रवैये और केंद्र सरकार के रुख की तुलना करते हुए सुधांशु ने एक घटना का उदाहरण दिया जब कोलकाता की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक इंतजार किया ताकि उनके सुरक्षा काफ़िले की वजह से नीट केंद्रों की ओर जा रहे छात्रों को ट्रैफिक की वजह से कोई परेशानी न हो।

सुधांशु ने कहा, एक तरफ़ प्रधानमंत्री हैं जो छात्रों की ज़रूरतों का इतना ध्यान रखते हैं, वहीं कांग्रेस परीक्षा देने वाले छात्रों के तनाव की परवाह किए बिना अपनी राजनीतिक छवि को प्राथमिकता देती है। प्रेट्र के अनुसार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके. हरिप्रसाद ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा नीट- यूजी में शामिल होने वाले कुछ छात्रों को ट्रैफिक जाम के कारण समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में हुई दिक्कतों पर अफसोस जताया।

कर्नाटक की कलह में भाजपा नेतृत्व की दो टूक, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली/ जीएनएस। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में जनता दल सेक्यूलर के प्रत्याशी की हार के बाद गठबंधन में उपजते दिख रहे अविश्वास और भाजपा विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोपों को पार्टी हाईकमान ने गंभीरता से लिया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य इकाई के अध्यक्ष वीवाई विजयेंद्र और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक को तलब कर सारे मामले की समीक्षा की। भाजपा नेताओं ने जेडीएस के पास जीत के पर्याप्त संख्या न होने सहित कई बिंदु अपनी सफाई में प्रस्तुत किए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष नवीन ने दो टूक कह दिया कि गठबंधन सहयोगी के साथ तालमेल हर हाल में बेहतर रहना चाहिए। अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कर्नाटक में हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में भाजपा के दो प्रत्याशी तो जीत गए, जबकि उसके सहयोगी घटक दल जेडीएस के प्रत्याशी की हार हो गई। इसके बाद से राज्य की राजनीति इन आरोपों के साथ उफान ले रही है कि भाजपा के कुछ विधायकों ने जेडीएस प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की है।

निस्संदेह इन परिस्थितियों ने कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी चिंतित कर दिया और वह अपने स्तर से मामले की तह तक जाने के प्रयास में हैं। चूंकि, जेडीएस राज्य के साथ केंद्र सरकार में भी भाजपा की गठबंधन सहयोगी है, इसलिए भाजपा हाईकमान ने भी इस मुद्दे को तुरंत हाथ में ले लिया और राज्य के नेताओं को दिल्ली बुला लिया।

मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य भाजपा अध्यक्ष वीवाई विजयेंद्र, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक और राष्ट्रीय महासचिव व कर्नाटक प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल के साथ बैठक कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

सूत्रों के अनुसार, राज्य के नेताओं ने दलील दी कि भाजपा के 64 विधायक हैं। 28-28 मतों के साथ पार्टी के दो प्रत्याशी जीत गए, लेकिन जेडीएस के पास जीत के लिए पर्याप्त संख्या ही नहीं थी। उसके 18 विधायक हैं। भाजपा के शेष आठ विधायकों के मत मिलाकर भी संख्या 26 रह जाती है। साथ ही यह तर्क भी दिया कि यदि जेडीएस का चुनाव प्रबंधन ठीक होता तो संख्या पूरी हो सकती थी।

जेडीएस की ओर से भाजपा पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है लेकिन खुद अपने विधायकों का वोट नहीं ले पाया।

होर्मुज संकट का भारत में तेल पर कितना असर? LNG की नहीं हुई कमी, रिपोर्ट में बड़ा दावा

नई दिल्ली/ जीएनएस। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भू-राजनीतिक तनाव और हार्मुज जलमार्ग के बंद होने से भारी उथल पुथल के बावजूद भारत ने अपनी एलएनजी आपूर्ति को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी एलएनजी खरीदार भारत ने विविध स्रोतों से आयात बढ़ाकर आपूर्ति बाधा को कम कर दिया, लिहाजा देश के भीतर उतनी संकट पैदा नहीं हुई जितना कि हो सकती थी।

वैश्विक आर्थिक शोध संस्थान एसएंडपी ग्लोबल इनर्जी की तरफ से 23 जून, 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, हार्मुज जलमार्ग के बंद होने से वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में करीब 17 फीसद की कटौती हुई, लेकिन अप्रैल-मई के माह में भारत का एलएनजी आयात लगभग सामान्य स्तर पर ही रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आयात में अप्रैल में मात्र 5 फीसद व मई में दो फीसद की गिरावट हुई है। रिपोर्ट में इसके लिए विभिन्न स्रोतों से आयात करने की नीति को सबसे बड़ा कारण बताया गया है। भारत ने ओमान, अमेरिका, नाइजीरिया और अंगोला जैसे वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाकर जोखिम को कम किया।

एसएंडपी ग्लोबल इनर्जी के प्रमुख शोध कर्ता जोहन उतामा ने बताया कि, ÷विभिन्न स्रोतों से एलएनजी लेने की भारत इस विविधीकृत रणनीति को भविष्य में भी बनाए रख सकता है, जो लंबी अवधि की सोर्सिंग रणनीतियों को भी प्रभावित करेगा।÷ रिपोर्ट में भारत की तारीफ करते हुए कहा गया है कि इस तरह की नीति वैश्विक अनिश्चितता के समय ऊर्जा सुरक्षा के लिए मिसाल है।

अधिवक्ता कल्याण, आधुनिक बार और मजबूत प्रतिनिधित्व का विजन लेकर मैदान में उतरे राजेश खंडेलवाल

अध्यक्ष पद प्रत्याशी ने जारी किया विस्तृत दृष्टिपत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटलीकरण, महिला सुविधाओं, युवा अधिवक्ताओं के सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास को बताया प्राथमिकता

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर जिला अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय में उत्साह और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। चुनावी सरगर्मियों के बीच अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने अपना विस्तृत विजन दस्तावेज जारी करते हुए अधिवक्ताओं के हितों, बार के आधुनिकीकरण और संस्थागत विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अधिवक्ता समुदाय अनेक नई चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसी परिस्थितियों में बार की भूमिका केवल प्रशासनिक संस्था तक सीमित नहीं रह सकती। बार को अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, उनके कल्याण, पेशागत विकास और सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी मंच बनना होगा।

राजेश खंडेलवाल ने कहा कि न्याय व्यवस्था की सफलता में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अधिवक्ता न केवल न्यायालयों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि विधि के शासन और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बावजूद अधिवक्ता समुदाय लंबे समय से स्वास्थ्य सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं, तकनीकी संसाधनों और संस्थागत सहयोग से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने दृष्टिपत्र में कई ऐसी योजनाओं को शामिल किया है, जिनका उद्देश्य अधिवक्ताओं के कार्य वातावरण और जीवन स्तर दोनों में सकारात्मक सुधार लाना है।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए व्यापक बीमा एवं मेडिक्लेम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिवक्ता समुदाय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उनका मानना है कि एक स्वस्थ अधिवक्ता ही न्याय व्यवस्था में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

राजेश खंडेलवाल ने बार के आधुनिकीकरण को समय की मांग बताते हुए कहा कि आज का दौर डिजिटल तकनीक का दौर है और बार को भी उसी अनुरूप विकसित करना होगा। उन्होंने बार के डिजिटलीकरण, डिजिटल सूचना प्रणाली, लॉयर्स हेल्प डेस्क, लॉयर्स हैंडबुक तथा अधिवक्ताओं को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली व्यवस्थाओं को विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी संसाधनों का उपयोग न केवल कार्यक्षमता बढ़ाएगा बल्कि अधिवक्ताओं का समय और श्रम भी बचाएगा।

बार परिसर में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अधिवक्ताओं को ऐसा कार्य वातावरण मिलना चाहिए जो गरिमापूर्ण, सुविधाजनक और आधुनिक हो। इसी उद्देश्य से वातानुकूलित बार कार्यालय, आधुनिक एवं हाईटेक वॉशरूम, विश्राम कक्ष, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, वाटर कूलर, ग्रीन नेट तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि बार परिसर केवल बैठकों और प्रशासनिक गतिविधियों का स्थान नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं के दैनिक कार्य और संवाद का प्रमुख केंद्र है। इसलिए इसकी आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है।

महिला अधिवक्ताओं की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विशेष सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना बार की जिम्मेदारी है। उनके लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के अपने पेशागत दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

युवा अधिवक्ताओं के भविष्य को लेकर भी राजेश खंडेलवाल ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। उन्होंने कहा कि नए अधिवक्ताओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसरों की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से नियमित विधिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषज्ञ व्याख्यानों तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उनका मानना है कि युवा अधिवक्ताओं को मजबूत बनाना बार के भविष्य को मजबूत बनाने के समान है।

अधिवक्ताओं की आर्थिक आवश्यकताओं और पेशागत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके दृष्टिपत्र में ?12,000 की फर्नीचर सहायता योजना, पारदर्शी चेंबर आवंटन व्यवस्था तथा अधिवक्ता सहायता तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिवक्ता टास्क फोर्स के गठन का भी प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने कहा कि बार को ऐसे संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है जो प्रत्येक अधिवक्ता तक सहायता और सहयोग पहुंचा सके।

शिक्षा और प्रतिभा के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेधावी छात्र सम्मान योजना को भी उनके विजन दस्तावेज में स्थान दिया गया है। उनका कहना है कि अधिवक्ता परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे अधिवक्ता समुदाय में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा।

राजेश खंडेलवाल ने कहा कि बार केवल न्यायिक गतिविधियों का केंद्र नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का भी महत्वपूर्ण मंच है। इसी सोच के साथ अधिवक्ता मैराथन, सामूहिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां और लंच व्यवस्था जैसे प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है। उनका उद्देश्य अधिवक्ताओं के बीच संवाद, सहयोग और एकजुटता को और अधिक मजबूत बनाना है।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्ताओं के हितों और सम्मान की रक्षा के लिए वे सदैव उपलब्ध रहेंगे। जब भी किसी अधिवक्ता साथी को उनकी आवश्यकता होगी, वे हरसंभव सहयोग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उनके अनुसार बार का नेतृत्व केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अधिवक्ता समाज के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व भी है।

अंत में राजेश खंडेलवाल ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि अधिवक्ता समुदाय की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को प्रभावी मंच प्रदान करने का प्रयास है। उन्होंने अधिवक्ता साथियों से समर्थन और विश्वास की अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें सेवा का अवसर प्राप्त होता है तो वे पारदर्शिता, जवाबदेही और समर्पण के साथ बार के विकास तथा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।

राजस्व न्यायालय के आदेश का अमल नहीं करने पर पटवारी को किया गया निलंबित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में राजस्व, पुलिस, भरण-पोषण, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद एवं अन्य विभागों से जुड़े अनेक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और आपातकालीन विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, ताकि जरूरतमंदों को समय पर राहत मिल सके। जनसुनवाई के दौरान कई जरूरतमंद नागरिक गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सहायता की मांग लेकर पहुंचे। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों ने इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर श्री वर्मा ने ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके। जनसुनवाई में भरण-पोषण से जुड़े कई प्रकरण भी सामने आए, जिनमें पारिवारिक विवाद, गुजारा भत्ता और घरेलू समस्याओं से संबंधित आवेदन शामिल थे। इसके साथ ही राजस्व संबंधी मामलों में नामांतरण, सीमांकन, अतिक्रमण, भूमि विवाद तथा लंबित आदेशों के पालन से जुड़े प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए। पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों में विवाद, सुरक्षा और अन्य मामलों को लेकर आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई के दौरान एक गंभीर शिकायत सामने आई, जिसमें राजस्व न्यायालयीन आदेश के पालन में एक पटवारी द्वारा बेवजह की देरी तथा अवांछित मांग किए जाने का आरोप लगाया गया। कलेक्टर श्री वर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया। आदेश जारी होने के बावजूद दो माह तक उसका पालन नहीं किया जाना प्रशासनिक लापरवाही और गंभीर अनियमितता माना। इस पर संबंधित क्षेत्र बिचौली हप्सी में पदस्थ पटवारी अनुशील जोसेफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही विभागीय जांच करने के आदेश भी जारी किए गए। इसके अलावा आवेदक के लंबित आदेश का पालन आज ही सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि शासन के आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जा रही है और जिन मामलों में अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही सामने आएगी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, श्री रोशन राय, श्री रिंकेश वैश्य सहित अन्य जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और मौके पर ही कई मामलों का निराकरण किया गया।

बेहतर पुलिसिंग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लागू की गई मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी समर्पण और दक्षता के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में जनवरी 2026 से पुलिस थानों एवं एसीपी कार्यालयों के कार्यों की एक मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत विभिन्न मापदंडों के आधार पर प्रत्येक जोन के पुलिस थानों और एसीपी कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा कर मासिक मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बनाना है।

माह मई 2026 के मूल्यांकन में सभी 12 एसीपी कार्यालयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एसीपी मल्हारगंज कार्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं शहर के सभी थानों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए थाना चंदन नगर प्रथम तथा थाना कनाड़िया द्वितीय स्थान पर रहा।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आयोजित सम्मान समारोह में पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने एसीपी मल्हारगंज श्री विवेक सिंह चौहान, थाना प्रभारी चंदन नगर श्री तिलक करोले, थाना प्रभारी कनाड़िया श्री सहर्ष यादव, उप निरीक्षक मनोज भदौरिया तथा आरक्षक रवि पांडे को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने से पूरी पुलिस टीम में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और बेहतर कार्य संस्कृति विकसित होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पहल पुलिसिंग की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी तथा आमजन को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भाजपा ने किया नमन, 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत किया पौधारोपण

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने पितृ पुरुष एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने राऊ नगर परिषद स्थित डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चावड़ा ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 23 जून 1953 को अखंड भारत की अवधारणा और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी एक महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी विचारक थे, जो एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करना चाहते थे। चावड़ा ने कहा कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉ. मुखर्जी ने देश में वैचारिक राजनीति की नई शुरुआत की थी। उन्होंने उस समय जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 370 का विरोध करते हुए एक देश, एक प्रधान, एक विधान का उद्घोष किया था। इसी उद्देश्य से वे कश्मीर गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। जेल में ही 23 जून 1953 को उनका निधन हुआ, जिसे भाजपा उनके बलिदान के रूप में स्मरण करती है।

उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के सपनों को साकार होने में 66 वर्ष लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सुरक्षित भारत के संकल्प को मजबूती मिली।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। उपस्थित जनों ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में जिला महामंत्री रामस्वरूप गहलोत, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र मंडले, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती पप्पी विजय पाटीदार, शिवनारायण डिंगू, घनश्याम नारोलिया, खेमचंद मित्तल सहित भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर इंदौर प्रशासन सख्त, 13 से अधिक संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए किया गया सील

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा सोमवार को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में तथा लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद इंदौर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर के कोचिंग सेंटरों, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में भंवरकुआं और गीता भवन क्षेत्र में एक ही दिन में 13 से अधिक संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया। प्रशासनिक टीम ने सबसे पहले भंवरकुआं स्थित कैटेलाइजर कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। यहां फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं। जांच के दौरान आग से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं मिले और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। इसके पश्चात एसडीएम श्री घनश्याम धनगर के नेतृत्व में टीम रेज़ोनेंस कोचिंग सेंटर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि संस्थान को करीब तीन माह पूर्व नोटिस जारी कर खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी सुधार नहीं किया गया।

अनूठी कला के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश, वेंट्रिलोक्विस्ट अंकित सिंह सिसोदिया ने किया जागरूक

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा एक विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री आर.के. सिंह एवं पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में किया गया।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध वेंट्रिलोक्विस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट एवं स्टैंड-अप कॉमेडियन अंकित सिंह सिसोदिया ने अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने लोकप्रिय कैरेक्टर ÷चिंटू÷ के साथ मनोरंजक और संवादात्मक अंदाज में सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत किया।

अंकित सिंह सिसोदिया और चिंटू के बीच हुए रोचक संवाद एवं हास्यपूर्ण वाद-विवाद के माध्यम से हेलमेट पहनने के महत्व, रॉन्ग साइड वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने, रेड लाइट और अन्य यातायात संकेतों का पालन करने जैसे आवश्यक नियमों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया गया।

प्रस्तुति के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर समाज में प्रचलित भ्रांतियों और वास्तविक तथ्यों पर भी चर्चा की गई। हास्य और मनोरंजन के माध्यम से दिए गए संदेशों ने उपस्थित लोगों को गहराई से प्रभावित किया। कार्यक्रम के अंत में नागरिकों ने स्वीकार किया कि यातायात नियम किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम हैं।

सड़क सुरक्षा जागरूकता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने अंकित सिंह सिसोदिया को प्रशस्ति-पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री आर.के. सिंह, पुलिस उपायुक्त (यातायात) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, अन्य पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक प्रहरी, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

यातायात प्रबंधन पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिवार तथा समाज को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाएं, क्योंकि सड़क पर आपकी एक सही आदत किसी का जीवन बचा सकती है।

जनसुनवाई बनी जनविश्वास का सशक्त माध्यम, पुलिस कमिश्नर ने सुनीं 90 आवेदकों की समस्याएं

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में मंगलवार को पुलिस कमिश्नर नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के शीघ्र, निष्पक्ष एवं न्यायोचित निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनसुनवाई में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें पारिवारिक विवाद, पति-पत्नी के मध्य मतभेद, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं से जुड़ी शिकायतें, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर एवं ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी ऋण लिए जाने की शिकायतें, किरायेदार एवं लेन-देन संबंधी विवाद, भूमि, प्लॉट एवं मकान से संबंधित धोखाधड़ी, लंबित शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने संबंधी आवेदन सहित अन्य पुलिस संबंधी प्रकरण प्रमुख रूप से शामिल रहे।

पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं और पीड़ा को धैर्यपूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। कई मामलों में उन्होंने दूरभाष पर अधिकारियों से चर्चा कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र राहत और न्याय मिल सके। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्री मयंक अवस्थी सहित सभी जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए 58 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित, 30 लाख की लूट का खुलासा करने वाली टीम को मिला विशेष पुरस्कार

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बेहतर पुलिसिंग और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए शुरू किए गए साप्ताहिक पुरस्कार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 58 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी समर्पण और दक्षता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

पलासिया स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने पुलिस थाना पंढरीनाथ क्षेत्र में हुई लगभग 30 लाख रुपये की लूट का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया। पुलिस टीम ने मामले में अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया तथा लूटी गई राशि में से 22.60 लाख रुपये बरामद करने में सफलता हासिल की।

सम्मानित टीम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 श्री दीशेष अग्रवाल, सहायक पुलिस आयुक्त सराफा श्री विजय तिवारी सहित पंढरीनाथ, चंदन नगर, भंवरकुआं, छत्रीपुरा, रावजी बाजार, जूनी इंदौर, सराफा थाना और साइबर सेल के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया।

कार्यक्रम में अन्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। थाना गांधीनगर की टीम को एक गंभीर अपराध के आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करने के लिए सराहा गया। थाना सदर बाजार के आरक्षक रामप्रसाद दांगी को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए सम्मानित किया गया। वहीं थाना तेजाजी नगर की टीम को अवैध गैस टंकी विक्रय करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया।

थाना तिलक नगर के पुलिसकर्मियों को चोरी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी, जबकि थाना तुकोगंज की टीम को वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 14 दोपहिया वाहन बरामद करने के लिए सम्मानित किया गया। अपराध शाखा के पुलिसकर्मियों को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं एमडी ड्रग्स तथा ब्राउन शुगर की बरामदगी के लिए पुरस्कृत किया गया।

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान राजबाड़ा पैलेस क्षेत्र में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सफलतापूर्वक संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री दीशेष अग्रवाल, सहायक पुलिस आयुक्त श्री विजय तिवारी तथा थाना सराफा के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।

इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों पर बेहतर यातायात प्रबंधन, नीट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सहायता, वीवीआईपी ड्यूटी, विशेष चालानी अभियान, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण तथा सड़क सुरक्षा अभियानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 यातायात पुलिसकर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

सड़क सुरक्षा के लिए इंदौर पुलिस का अभियान जारी, 33वें चरण तक 4,450 से अधिक हेलमेट वितरित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का सड़क सुरक्षा जनजागरूकता अभियान लगातार जारी है। पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर.के. सिंह एवं पुलिस उपायुक्त यातायात श्री राजेश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यह अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 23 जून 2026 को पलासिया चौराहे पर इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 33वां हेलमेट पहनेंङ्कसुरक्षित रहें वृहद जनजागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री राजेश कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त यातायात श्री राजेश कुमार त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अभियान के दौरान ऐसे दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए, जिनके वाहन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण पाए गए। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई तथा उन्हें सड़क सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट भी प्रदान किए गए, ताकि भविष्य में वे अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक सजग रहें।

इस अवसर पर उन जिम्मेदार वाहन चालकों को भी सम्मानित किया गया, जो स्वेच्छा से हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन करते हुए पाए गए। उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप उपहार प्रदान किए गए।

इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित 33 हेलमेट जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 4,450 से अधिक हेलमेट जरूरतमंद वाहन चालकों को वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सुरक्षित यातायात के लिए जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित ट्रैफिक प्रहरी अभियान से अब तक 3,915 नागरिक जुड़ चुके हैं।

एक करोड़ की लहसुन चिप्स की कीमत हो गई दो करोड़! धोखाधड़ी कर लहसुन हड़पने के आरोपी की 7 माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं

सीएम हेल्पलाइन सहित एसपी को जनसुनवाई में शिकायत के बाद भी नही मिला न्याय, आरोपी पर खुलेआम घूमने व धमकी देने का आरोप

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की लहसुन चिप्स के कथित गबन एवं धोखाधड़ी के मामले में दर्ज अपराध के आरोपी की सात माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से फरियादी पक्ष में काफी आक्रोश है। इस बीच आरोपी द्वारा हड़पी गई लहसुन की कीमत वर्तमान में दुगुनी हो गई है। पिपलिया मंडी निवासी फरियादी ने पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देने तथा कार्रवाई में जानबूझकर देरी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक पहुंच और प्रभावशाली रसूख के कारण आरोपी कानून की गिरफ्त से बाहर है, जबकि शिकायतकर्ता न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। फरियादी पक्ष का आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जिला पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई सहित विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। मामले में आरोपी खुलेआम घूम रहा है, अपना व्यापार कर रहा है और शिकायतकर्ताओं को धमकाने का प्रयास भी कर रहा है। फरियादी का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इसी प्रकार की लापरवाही से समाज में हत्या, आत्महत्या और अन्य गंभीर अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं।

वर्षों पहले कोल्ड स्टोरेज में रखा था माल- प्रकरण के अनुसार पिपलियामंडी निवासी सुनिल जैन एवं उनके भाई दिलीप जैन लहसुन चिप्स के व्यापार से जुड़े हुए हैं। दोनों भाइयों ने वर्ष 2019 से 2021 के दौरान मंदसौर के औद्योगिक क्षेत्र जग्गाखेड़ी स्थित नाकोड़ा कोल्ड स्टोरेज एवं आइस प्लांट में बड़ी मात्रा में लहसुन चिप्स भंडारित किया था। फरियादियों के अनुसार विभिन्न रसीदों के माध्यम से कुल 3507 बैग लहसुन चिप्स कोल्ड स्टोरेज में जमा कराए गए थे। इनमें कुछ माल की पक्की रसीदें उपलब्ध हैं, जबकि कुछ माल के लिए संचालक द्वारा कच्ची रसीदें देकर बाद में पक्की रसीद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। वर्षों तक माल सुरक्षित रखने के भरोसे पर व्यापारियों ने अपना माल वहां जमा रखा।

माल बेचने का सौदा हुआ तो सामने आया पूरा मामला- फरियादी सुनिल जैन ने बताया कि वर्ष 2025 में उन्होंने उक्त लहसुन चिप्स को पिपलियामंडी की एक फर्म को लगभग 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का सौदा किया था। सौदे के अनुसार अगस्त 2025 तक माल की डिलीवरी देना थी। इसके लिए उन्होंने नाकोड़ा कोल्ड स्टोरेज के संचालक संदीप पिता रमेशचन्द्र चौधरी, निवासी नीमच से संपर्क कर अपना माल वापस मांगा। आरोप है कि संचालक लगातार दो-चार दिन का समय मांगकर उन्हें टालता रहा। जब कई बार मांग करने के बाद भी माल नहीं मिला तो फरियादी स्वयं जग्गाखेड़ी स्थित कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि कोल्ड स्टोरेज लगभग खाली हो चुका है और संचालक वहां से माल हटाकर चला गया है।

1 करोड़ का माल की कीमत हुई 2 करोड रुपए- फरियादियों का आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज में जमा 3507 बैग लहसुन चिप्स, जिसकी कीमत उस समय एक करोड रुपए थी । लेकिन वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार यह राशि करीब दो करोड़ रुपये तक पहुंचती है। उक्त लहसुन को संचालक द्वारा कपटपूर्वक हड़प लिया गया। माल की मांग करने पर लगातार बहाने बनाए गए और आज तक न तो माल लौटाया गया और न ही उसकी कीमत का भुगतान किया गया। फरियादी पक्ष का कहना है कि यह केवल व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और विश्वासघात का गंभीर मामला है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

नवम्बर 2025 में दर्ज हुआ था मामला- मामले की शिकायत करने के एक माह बाद पुलिस थाना वायडी नगर, मंदसौर में 4 नवंबर 2025 को अपराध क्रमांक 489/2025 दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए आरोपी संदीप चौधरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना प्रारंभ की। फरियादी का कहना है कि अपराध दर्ज होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस शीघ्र कार्रवाई करेगी, लेकिन सात माह बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

पुलिस पर मिलीभगत के लगाए आरोप- फरियादी के भाई अनिल जैन ने भी उच्च अधिकारियों को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ताओं को ही बार-बार थाने बुला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनसे लगातार नए-नए गवाह और दस्तावेज मांग रही है, जबकि आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा। आवेदन में कहा गया है कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्कों का उपयोग कर मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। इसी कारण पुलिस भी उसके विरुद्ध कार्रवाई करने से बच रही है। फरियादी परिवार ने मांग की है कि आरोपी संदीप चौधरी को तत्काल गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाए तथा गबन किए गए माल या उसकी राशि की वसूली कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने की भी मांग की गई है।

सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में भी लगाई गुहार- फरियादी पक्ष ने बताया कि न्याय की उम्मीद में उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसका संतोषजनक निराकरण नहीं हुआ। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में भी आवेदन प्रस्तुत कर आरोपी की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। फिलहाल मामला पुलिस विवेचना में है, लेकिन सात माह बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है।

आरोप गलत, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी- वायडीनगर थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने फरियादी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा गंभीरता से की जा रही है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी के अनुसार मामले में फरियादी द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ बिलों एवं दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव में कार्य नहीं करती है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई जारी है तथा उसके संभावित ठिकानों पर भी पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पेयजल संकट से परेशान वार्ड 13 के रहवासी पहुंचे जनसुनवाई, नियमित और स्वच्छ पानी की मांग

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर के वार्ड क्रमांक 13 स्थित बगीचा नंबर-4 के रहवासियों ने लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से नियमित, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करते हुए जल्द समाधान की अपेक्षा जताई।

समाजसेविका शाहमिदा मिर्जा के नेतृत्व में प्रस्तुत ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड क्रमांक 13 के बगीचा नंबर-4 क्षेत्र में कई वर्षों से पेयजल संकट बना हुआ है।

क्षेत्र में पानी की आपूर्ति अनियमित है और कई बार नलों से गंदा एवं दूषित पानी आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रहवासियों का कहना है कि पानी की अनियमित आपूर्ति के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं दूषित पानी के कारण बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों को पेयजल के साथ-साथ घरेलू उपयोग के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशान होना पड़ रहा है।

ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि प्रतिदिन सुबह निर्धारित समय पर स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जलापूर्ति व्यवस्था और पाइपलाइन नेटवर्क की तकनीकी जांच कर आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र कराए जाएं, ताकि क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान हो सके। रहवासियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

अवैध खनिज उत्खनन परिवहन पर तीन वाहन मालिकों पर कुल 84 हजार से अधिक का जुर्माना अधिरोपित

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन के तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 84 हजार 100 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 0045/अ-67/2026-27- में पारित आदेशानुसार पुलिस थाना मनासा द्वारा जप्त जे.सी.बी. क्रमांक MP14GC0317 में बिना रॉयल्टी मुरूम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक पवन पिता जीतमल मोग्या निवासी सावन पर 45000 रूपये की शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 22500 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 22500 रूपये शामिल है।

प्रकरण क्रमांक 0048/अ-67/2026-27- में पारित आदेशानुसार ग्राम चौथखेडा तहसील नीमच में मुरूम का उत्खनन पर वाहन मालिक रामचरण पिता नाथूलाल गुर्जर निवासी चौथखेडा पर 10500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 5250 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 5250 रूपये शामिल है।

प्रकरण क्रमांक 0049/अ-67/2026-27- पारित आदेशानुसार ग्राम सुवाखेडा में ट्रेक्टर क्र. MP44ZA7683, बिना रॉयल्टी के खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पर वाहन मालिक सुरेश पिता शांतिलाल निवासी सुवाखेडा तहसील जावद जिला नीमच पर 28600 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3600 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है। सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है।

जेतपुरा लूटकांड से पुलिस पर उठे सवाल, कांग्रेस ने कहा- 'मल्हारगढ़ पुलिस की नाकामी से अपराधियों के हौसले बुलंद'

पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता, लूट को चोरी बताने और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताया आक्रोश

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जेतपुरा में महिला के साथ चाकू की नोक पर हुई लूट की वारदात ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के कई दिन बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने मल्हारगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा और प्रदेश कांग्रेस संयुक्त सचिव मुकेश निडर ने जेतपुरा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा घटना की पूरी जानकारी ली। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चोरों और लुटेरों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि अब वे रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुसकर हथियारों के बल पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। पीड़ित परिवार के अनुसार रात करीब एक बजे तीन नकाबपोश बदमाश किचन की खिड़की तोड़कर घर में घुस आए। बदमाशों ने महिला विधवा महिला गट्टूबाई पाटीदार के गले पर

चाकू रखकर उसे धमकाया और घर में रखी नकदी व आभूषण लूट लिए। महिला ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने कथित रूप से अपने साथियों से कहा कि इसे गोली मार दो। इस धमकी से महिला भयभीत हो गई और बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

परिजनों के अनुसार आरोपी लगभग 30 हजार रुपये नकद, करीब डेढ़ लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण तथा एक कीपैड मोबाइल फोन लेकर भाग गए। जिस मोबाइल में सक्रिय सिम लगी हुई थी और वह घटना के बाद भी चालू बताया जा रहा था, उसकी लोकेशन के आधार पर भी पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट रूप से लूट की घटना है, क्योंकि बदमाशों ने महिला को हथियार दिखाकर डराया व धमकाया और उसके शरीर से जेवर उतरवाए। इसके बावजूद पुलिस मामले को चोरी बताकर उसकी गंभीरता कम करने का प्रयास कर रही है। नेताओं का कहना है कि यदि किसी महिला के गले पर चाकू रखकर आभूषण छीने जाएं तो उसे साधारण चोरी नहीं बल्कि लूट माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसी रात गांव में किशनलाल पाटीदार और वजेराम मालवी के घरों के ताले भी तोड़े गए थे, जिससे स्पष्ट है कि अपराधियों का गिरोह सक्रिय है और गांवों को निशाना बना रहा है। इसके बावजूद पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। अनिल शर्मा और मुकेश निडर ने कहा कि मल्हारगढ़ क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं के कारण आम जनता में भय का वातावरण है। लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कोई ऐसा मामला होता जिसमें पुलिस की विशेष रुचि रहती है तो कार्रवाई तेजी से होती, लेकिन आम लोगों के घरों में हुई चोरी और लूट के मामलों में पुलिस की सक्रियता दिखाई नहीं देती। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देशभक्ति जनसेवा का नारा देने वाली पुलिस जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और क्षेत्र में अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी तथा मामले को उच्च स्तर तक उठाएगी। इस अवसर पर ग्रामीण कन्हैयालाल पाटीदार, बंटी राजपूत, पप्पू मालवीय, जीवन पटेल, समरथ पाटीदार, विनोददास बैरागी आदि मौजूद थे। मल्हारगढ थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी कहना है कि केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है और चोरी गए मोबाइल फोन की लोकेशन सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कुछ संदिग्ध आरोपियों की तलाश की जा रही है।

करोड़ो की नगर पालिका में पेयजल संकट, घटिया सड़क निर्माण की अनियमितताओं व सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में लगातार गहराते पेयजल संकट, अव्यवस्थित जल प्रदाय व्यवस्था,निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं तथा सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर नगर पालिका परिषद मंदसौर में नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी व सभी कांग्रेस के पार्षगण के नेतृत्व मे जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को नगर पालिका परिषद मंदसौर पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के ज्ञापन लेने नहीं पहुंचने पर ज्ञापन की प्रति नगर पालिका के गेट पर ही चस्पा कर नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया।

नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती रफत पयामी ने ज्ञापन में बताया गया कि करोड़ों रुपये की लागत से संचालित पेयजल योजना के बावजूद शहरवासियों को पर्याप्त एवं नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रेशर नहीं होने के कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जर्जर पाइपलाइन, विद्युत बाधा और तकनीकी खामियों के कारण जल आपूर्ति लगातार प्रभावित हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने खानपुरा, पुराना किला क्षेत्र, गुदरी,शेखा चौक, कुम्हारवाड़ा, बोहरा बावड़ी, शुक्ला चौक, जनकूपुरा, नीलगर चौक, इंदिरा कॉलोनी, सीतामऊ फाटक, टोडी एवं बंजारा बस्ती सहित अनेक क्षेत्रों में व्याप्त जल संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि कई संकरी गलियों में पानी के टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । ज्ञापन में शहर में निर्माणाधीन एवं हाल ही में निर्मित सीसी सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए । वही ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि

नगर के शहर क्षेत्र में नई टंकी का निर्माण किया जाए,अभी वर्तमान में शहर में जल प्रदाय व्यवस्था में समय की जो कटौती की गई है उसको खानपुरा और शहर क्षेत्र की सकरी गलियों वाले एरिया में लागू नहीं किया जाए,शहर की पुरानी हो चुकी 50 साल पुरानी पाइप लाइनों को बदल जाए । कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर नई सड़कें अल्प समय में ही क्षतिग्रस्त होने लगी हैं, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है । उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की । साथ ही गांधी चौराहे के समीप एक पेड़ काटे जाने की घटना पर भी कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। नेताओं ने कहा कि एक ओर लाखों रुपये खर्च कर पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिना पर्याप्त कारण के वृक्षों की कटाई पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करती है । मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई । कांग्रेस नेताओं ने शहर की सफाई व्यवस्था को भी अपर्याप्त बताते हुए कहा कि कई वार्डों में नियमित सफाई नहीं होने से नागरिकों को गंदगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नगर पालिका प्रशासन से पेयजल संकट, सड़क निर्माण की गुणवत्ता, वृक्ष संरक्षण एवं सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। संचालन शैलेंद्र गोस्वामी ने किया व कार्यक्रम का आभार कमलेश सोनी ने माना।

दशपुर अकाउंटेंट एसोसिएशन की बैठक संपन्न, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंदसौर और पिपलिया मंडी के अकाउंटेंट्स की प्रमुख संस्था दशपुर अकाउंटेंट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय दशपुर कुंज में आयोजित की गई। बैठक के दौरान संस्था के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न आवश्यक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। इस बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित काबरा के साथ उपाध्यक्ष प्रभुलाल जैन, सचिव महेश सोलंकी और कोषाध्यक्ष हेमंत जैन सहित संस्था के सक्रिय सदस्य अभय नाहर, लक्ष्मीनारायण गोयल, यशवंत गोयल, संदीप डांगी, अजय फांफरिया, नितिन गर्ग, चंद्रेश बाफना, मोहनलाल कुमावत, कैलाश सोनी और यशवंत पोखरना सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चर्चा में भाग लिया। बैठक के समापन पर सभी उपस्थित सदस्यों का आभार सचिव महेश सोलंकी द्वारा व्यक्त किया गया।

प्रेस वार्ता : पेपर लीक माफिया से उनके संबंध की मांग उठाई जाएगी

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नीट पेपर लीक की घटना के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छात्रो की गुंज अभियान शुरु किया है। पिछले दिनो इसी अभियान के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोटा में छात्र संवाद भी किया। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में युवक कांग्रेस एवं एनएसयुआई द्वारा आगामी 25 जुन से 9 अगस्त तक देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा । इस दौरान शिक्षामंत्री का इस्तीफा तथा पेपर लीक माफिया से उनके संबंध की मांग उठाई जाएगी।

यह जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्रसिंह गुर्जर ने मंगलवार को मंदसौर जिला कांग्रेस में मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होने बताया कि देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते दबाव और छात्रों पर पड़ रहे मानसिक एवं आर्थिक बोझ को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से युवाओं की आवाज उठाई गई। अभियान के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की समस्याओं को सामने रखा गया। प्रस्तुति में एक छात्रा की भावनात्मक कहानी साझा करते हुए बताया गया कि परीक्षा के दबाव और असफलता के डर के कारण कई विद्यार्थी मानसिक तनाव से गुजरते हैं। उन्होने बताया कि मेडिकल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों का खर्च करोड़ों रुपये तक पहुंच रहा है। कोचिंग, हॉस्टल, भोजन और अध्ययन सामग्री पर होने वाला व्यय आम परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है। उन्होने बताया कि नीट के विद्यार्थियों का निजी खर्च 1.32 लाख करोड होता है । जबकि भारत सरकार का शिक्षा बजट 1.4 लाख करोड का है । भारत की शिक्षा व्यवस्था वसुली तंत्र के समान हो गई है । उन्होने बताया कि पेपर लीक, पुनर्मूल्यांकन की समस्याएं, बढ़ती छात्र आत्महत्याएं और रोजगार संकट जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 25 से 9 अगस्त तक युवक कांग्रेस एवं एनएसयुआई द्वारा देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा । इसके तहत मंदसौर में भी छात्र संवाद, जनसम्पर्क अभियान, सोश्यल मीडिया अभियान, सार्वजनिक प्रस्तुतियां व प्रेस वार्ताएं के आयोजन किए जा रहे है । इस अभियान के दौरान परीक्षा परिणाम का पुर्नमुल्यांकन एवं सुधार, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तथा पेपर लीक माफिया से उनके संबंध की निष्पक्ष जांच एवं वार्षिक परीक्षा तथा भर्ती कैलेंडर को स्थागत स्वरुप प्रदान करने की मांग उठाई जाएगी । सवालो के जवाब में उन्होने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को केवल परीक्षा और शुल्क आधारित तंत्र नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के संगठन महासचिव अजय लोढा ने कहा कि अभियान के तहत छात्रों और अभिभावकों से सुझाव आमंत्रित किए जांएगे । इसके साथ ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग उठाई जाएगी जो युवाओं को बडे सपने देखने का अवसर दे । उनके सपनो को पुरा करने में मदद करे और कम लागत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए । शहर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष इष्टा भाचावत ने कहा कि नीट के विद्यार्थियों का निजी खर्च 1.32 लाख करोड होता है । जबकि भारत सरकार का शिक्षा बजट 1.4 लाख करोड का है । इस अवसर पर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गेश पटेल, कांग्रेस नेता प्रवीण मांगरिया, शहर ब्लाक युवक कांग्रेस अध्यक्ष सम्यक जैन भी मौजुद रहे।

कटोरा-हांडी लेकर जनसुनवाई पहुंचे किसान और सामाजिक कार्यकर्ता, बलराम योजना में गड़बड़ी का लगाया आरोप

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के विरोध का अनोखा दृश्य देखने को मिला। ग्राम तुर्किया, पंचायत धनगांव के किसान किशोर गुर्जर एवं सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी हाथों में कटोरा और हांडी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। दोनों ने गले में ÷बलराम योजना की 13वीं÷ लिखी तख्तियां पहन रखी थीं और योजना में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की।

जनसुनवाई के दौरान किसान किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि उनके खेत पर बलराम तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसके लिए उनके नाम पर 1 लाख 19 हजार 108 रुपये का भुगतान दर्शाया गया है। जबकि उनके अनुसार उनके बैंक खाते में केवल 15 हजार रुपये ही जमा हुए हैं। किसान ने शेष राशि के कथित गबन की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

किशोर गुर्जर ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में आरोप लगाया कि योजना के तहत हुए भुगतान और निर्माण कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, सरपंच, सचिव एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने तथा कथित रूप से हड़पी गई राशि की वसूली कराने की मांग की।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि बलराम योजना के कार्य को मनरेगा से जोड़कर शासन के 8 जनवरी 2020 के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। किसान ने पूरे मामले की तकनीकी एवं वित्तीय जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की।

वहीं सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी ने हाथ में हांडी लेकर विरोध जताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जांच शुरू नहीं हुई तो वे ÷अस्थि कलश-कटोरा सत्याग्रह÷ के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन शुरू करेंगे।

जनसुनवाई के दौरान कटोरा और हांडी के साथ किया गया यह विरोध प्रदर्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य योजना में हुई कथित अनियमितताओं को उजागर करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराना है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जांच के बाद वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।

सम्पादकीय

शहर किसके लिए: वाहन या नागरिक?

भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। महानगरों से लेकर मध्यम और छोटे शहरों तक शहरीकरण की गति अभूतपूर्व है। आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लाखों लोग प्रतिवर्ष शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। किंतु इस तीव्र शहरी विस्तार के बीच एक बुनियादी प्रश्न अक्सर उपेक्षित रह जाता है–क्या हमारे शहर अपने नागरिकों के लिए चलने योग्य हैं? क्या सड़कें केवल वाहनों के लिए हैं या मनुष्यों के लिए भी?

हाल ही में न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार से जोड़ते हुए मौलिक अधिकार की संज्ञा दिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गई हैं। यह एक स्वागत योग्य संवैधानिक प्रोत्साहन है, क्योंकि यह पहली बार शहरी अवसंरचना को केवल निर्माण और यातायात के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और मानव गरिमा के संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या केवल न्यायिक घोषणा या कानूनी मान्यता से भारतीय शहर वास्तव में पैदल यात्रियों के अनुकूल बन जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। वास्तविक परिवर्तन तब आएगा जब शहरी नियोजन की सोच वाहन-केंद्रित मॉडल से हटकर मानव-केंद्रित मॉडल की ओर अग्रसर होगी और समाज में पैदल चलने को सम्मानजनक एवं प्राथमिक परिवहन माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

भारत में पैदल चलना कोई सीमित गतिविधि नहीं है। विभिन्न सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार देश में बड़ी संख्या में दैनिक यात्राएँ पूरी या आंशिक रूप से पैदल ही की जाती हैं। गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएँ, बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिक सबसे अधिक पैदल यात्रा करते हैं। इसके बावजूद शहरी नियोजन में पैदल यात्रियों को सबसे कम प्राथमिकता मिलती है। अधिकांश शहरों में फुटपाथ या तो हैं ही नहीं, या इतने संकरे, टूटे हुए और अतिक्रमण से घिरे होते हैं कि उनका उपयोग करना कठिन हो जाता है। कई स्थानों पर फुटपाथ पार्किंग स्थल, दुकानों के विस्तार, ठेलों या निर्माण सामग्री के भंडारण में परिवर्तित हो जाते हैं।

इस स्थिति का सबसे दुखद परिणाम सड़क दुर्घटनाओं में दिखाई देता है। भारत विश्व में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मामले में अग्रणी देशों में है। इन दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या पैदल यात्रियों की होती है। सड़क पार करने, फुटपाथों की अनुपलब्धता और वाहनों की तेज गति के कारण हजारों लोग प्रतिवर्ष अपनी जान गंवाते हैं। यह केवल परिवहन का संकट नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का भी प्रश्न है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। समय के साथ न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या का दायरा बढ़ाते हुए स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे अधिकारों को भी इसमें शामिल किया है। सुरक्षित पैदल मार्गों का अधिकार इसी प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टिकोण का विस्तार है। जब कोई नागरिक अपने घर से विद्यालय, कार्यालय, अस्पताल या बाजार तक सुरक्षित रूप से नहीं पहुँच सकता, तब उसके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अधूरा रह जाता है। इसलिए फुटपाथ केवल सीमेंट और कंक्रीट की संरचना नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक हैं।

फिर भी केवल अधिकार की घोषणा पर्याप्त नहीं है। भारत में अनेक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त होने के बावजूद उनके क्रियान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और भोजन का अधिकार इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार फुटपाथ के अधिकार को भी व्यवहार में उतारने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति, वित्तीय निवेश और संस्थागत सुधार आवश्यक होंगे।

भारतीय शहरी शासन की सबसे बड़ी समस्या इसका वाहन-केंद्रित दृष्टिकोण है। स्वतंत्रता के बाद विकास का जो मॉडल अपनाया गया, उसमें चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवरों और एक्सप्रेसवे को आधुनिकता का प्रतीक माना गया। शहरों की सफलता को वाहनों की गति और सड़क क्षमता के आधार पर मापा गया। परिणामस्वरूप पैदल यात्री, साइकिल चालक और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ता हाशिए पर चले गए। नगर नियोजन का उद्देश्य लोगों की सुविधा के बजाय वाहनों की निर्बाध आवाजाही बन गया।

यह दृष्टिकोण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत है। भारत में निजी कारों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जबकि अधिकांश नागरिक सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल यात्रा पर निर्भर हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक धन का बड़ा हिस्सा उन परियोजनाओं पर खर्च होता है जो मुख्यतः वाहन मालिकों को लाभ पहुँचाती हैं। इससे संसाधनों के वितरण में असमानता बढ़ती है और गरीब वर्गों की गतिशीलता प्रभावित होती है। फुटपाथों की स्थिति लैंगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महिलाएँ, विशेषकर कामकाजी महिलाएँ और छात्राएँ, सुरक्षित और प्रकाशयुक्त पैदल मार्गों पर अधिक निर्भर रहती हैं। खराब फुटपाथ, अपर्याप्त रोशनी और असुरक्षित सार्वजनिक स्थान उनके आवागमन को सीमित करते हैं। इसी प्रकार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए बाधा-रहित फुटपाथ जीवन की आवश्यक शर्त हैं। यदि शहरी अवसंरचना इन समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती, तो शहर समावेशी नहीं कहे जा सकते।

मानव-केंद्रित शहरी नियोजन का विचार इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इसका मूल सिद्धांत है कि शहरों को वाहनों के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। सड़कें केवल यातायात गलियारे नहीं, बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक स्थान भी हैं। फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन और सार्वभौमिक पहुँच इस मॉडल के प्रमुख तत्व हैं।

विश्व के अनेक शहरों ने इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई शहरों ने पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी, वायु प्रदूषण में नियंत्रण और नागरिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार हासिल किया है। इन अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षित और चलने योग्य शहर केवल यातायात प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि समग्र शहरी विकास की रणनीति हैं।

भारत में भी कुछ सकारात्मक पहलें देखने को मिली हैं। कुछ शहरों ने 'कम्प्लीट स्ट्रीट्स' की अवधारणा को अपनाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत सड़कों को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित बनाया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी कई स्थानों पर फुटपाथों के विकास और सार्वजनिक स्थलों के पुनरोद्धार के प्रयास हुए हैं। किंतु इन पहलों का प्रभाव अभी सीमित है और वे व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन का रूप नहीं ले सकी हैं। इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। पहला, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता सीमित है। अधिकांश नगर निकाय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है। सड़क निर्माण, यातायात प्रबंधन, जल निकासी, बिजली और दूरसंचार से जुड़ी एजेंसियाँ अलग-अलग कार्य करती हैं, जिसके कारण फुटपाथ बार-बार खोदे जाते हैं और उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तीसरा, नागरिक सहभागिता का अभाव है। योजनाएँ अक्सर ऊपर से नीचे (ङ्गश्च-स्नश्च2ठ्ठ) दृष्टिकोण से बनाई जाती हैं, जिनमें स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।

फुटपाथों के अधिकार की सफलता के लिए केवल कानूनी उपायों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। न्यायालय किसी अधिकार की घोषणा कर सकते हैं और सरकारों को निर्देश दे सकते हैं, लेकिन शहरों के चरित्र को बदलने के लिए सामाजिक और प्रशासनिक परिवर्तन आवश्यक है। यह परिवर्तन सबसे पहले नीति-निर्माण में दिखाई देना चाहिए। शहरी परिवहन नीतियों में पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक सड़क परियोजना में फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

दूसरा, बजट आवंटन में परिवर्तन आवश्यक है। यदि नगर निकायों के अधिकांश संसाधन फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण पर खर्च होते रहेंगे, तो पैदल यात्री सुविधाएँ कभी प्राथमिकता नहीं बन पाएंगी। सार्वजनिक निवेश का एक निश्चित भाग गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। तीसरा, शहरी संस्कृति में बदलाव लाना होगा। भारतीय समाज में निजी वाहन, विशेषकर कार, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाते हैं। इसके विपरीत पैदल चलने को अक्सर मजबूरी समझा जाता है। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक नीति और व्यवहार में पैदल यात्रियों को उचित सम्मान नहीं मिल सकेगा। शहरों को इस विचार को बढ़ावा देना होगा कि पैदल चलना केवल गरीबों का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली का हिस्सा है।

हर शहर में सुलगती लापरवाही: क्या अगला लखनऊ आपका होगा?

जब कागजों की मंजूरियाँ और बंद लिफाफे सच को ढकने लगते हैं, तब आग केवल इमारतों तक सीमित नहीं रहती, वह व्यवस्था की आत्मा को भी झुलसा देती है। लखनऊ के अलीगंज की घटना किसी एक दिन की दुर्घटना नहीं, बल्कि उस लंबी लापरवाही का विस्फोट थी जिसमें सुरक्षा को हमेशा बाद में टाल दिया गया। इसी पृष्ठभूमि में एक तीखा सवाल उभरता है–जो अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि कठोर सामाजिक आरोप बन चुका है। यह सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं, बल्कि उस ढांचे का दर्पण है जहाँ शिक्षा धीरे-धीरे जोखिम और लाभ के बीच झूलता हुआ बाजार बन गई है।

22 जून 2026 की दोपहर ने लखनऊ के अलीगंज की एक साधारण सी इमारत को मौत के मंजर में बदल दिया। नीचे पेट शॉप और क्लिनिक की रोजमर्रा की हलचल थी, जबकि ऊपर कोचिंग सेंटर में भविष्य संवारने के सपने बुने जा रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में वह इमारत धुएं और आग के भयानक जाल में कैद हो गई। छात्र जान बचाने के लिए भागे, खिड़कियों तक पहुंचे, कुछ ने मजबूरी में छलांग लगाई, पर अधिकांश घने धुएं की दीवार में फंस गए। चीखें धीरे-धीरे खामोशी में घुल गईं। कम से कम 15 युवा जीवन, जो अभी सपनों को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे, ÷लखनऊ आग में 15 जवान सपनों की राख÷ बनकर हमेशा के लिए मिट गए।

यह हादसा किसी अचानक तकनीकी खराबी का नतीजा भर नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था की उपज था जिसने वर्षों तक चेतावनियों को अनसुना किया। जिस भवन में कोचिंग संचालित हो रही थी, उसे 2016 में अवैध निर्माण पर एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी हुआ था, जिसे दो महीने बाद वापस ले लिया गया था। फायर एनओसी मौजूद नहीं था, और आपातकालीन निकास या तो बंद पड़े थे या केवल औपचारिकता बनकर रह गए थे। खिड़कियों पर लगी लोहे की जालियाँ/ग्रिल्स बाहर निकलने में बाधक बनीं। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार एसी में संभावित शॉर्ट सर्किट सिर्फ एक चिंगारी थी, असली आग तो उस लापरवाही में थी जो वर्षों से सुलग रही थी। नीचे व्यापार की रफ्तार जारी थी और ऊपर जीवन दम तोड़ रहा था।

जैसे-जैसे हादसे की परतें खुलती गईं, वही पुराना और असहज करने वाला सवाल फिर सामने खड़ा हो गया–आखिर यह सब हुआ कैसे? अनुमति किसने दी, निरीक्षण किसने किया, और किसने जानबूझकर नजरें फेर लीं? यह केवल प्रशासनिक लापरवाही भर नहीं दिखती, बल्कि एक ऐसे तंत्र की ओर इशारा करती है जहाँ नियमों की कीमत तय होती है और सुरक्षा सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाती है। यह पैटर्न नया नहीं है। कोटा की आत्महत्याएँ, दिल्ली के राजेंद्र नगर की बेसमेंट बाढ़ और अब लखनऊ की यह अग्निकांड–हर जगह कहानी एक ही जैसी दिखती है- भीड़ बढ़ाओ, मुनाफा कमाओ और सुरक्षा को बाद के लिए छोड़ दो।

आज के दौर में छात्र केवल सीखने वाला नहीं रह गया, बल्कि एक चलती-फिरती आर्थिक इकाई में बदल चुका है। माता-पिता कर्ज के बोझ तले फीस चुकाते हैं, अपनी उम्मीदें गिरवी रखकर बच्चों का भविष्य ÷खरीदने÷ की कोशिश करते हैं। कोचिंग उद्योग इस मानसिक दबाव को बखूबी समझता है, इसलिए उसकी संरचना भी उसी अनुरूप गढ़ी जाती है–ऊंची दीवारें, नियंत्रित प्रवेश और अक्सर बंद पड़े आपात निकास। यही वह व्यवस्था है जिसने शिक्षा को धीरे-धीरे ऐसे तंत्र में बदल दिया है, जहाँ जीवन से अधिक महत्व उपस्थिति और फीस को मिलने लगता है।

हादसे के बाद प्रशासनिक प्रतिक्रिया भी उसी पुराने, परिचित ढर्रे पर आगे बढ़ी। जांच के आदेश जारी हुए, शोक संदेश दिए गए, मुआवजे की घोषणाएँ हुईं, कुछ गिरफ्तारियाँ और निलंबन भी हुए–जैसा हर बार होता आया है। मुख्यमंत्री स्तर से कार्रवाई के निर्देश आए, प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की, लेकिन यह संवेदना भी कुछ ही समय में औपचारिकता बनकर रह गई। असली प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रहे–क्या यह अंतिम हादसा होगा, या अगली त्रासदी की नींव पहले से ही रखी जा रही है? क्योंकि हर दुर्घटना के बाद यही चक्र दोहराया जाता है और समय के साथ समाज उसे भुला देने की आदत डाल लेता है।

अब प्रश्न व्यवस्था की कार्यप्रणाली नहीं, उसकी नींव की ईमानदारी पर है। कोचिंग सेंटरों को ÷शिक्षा का मंदिर÷ नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से व्यावसायिक इकाई मानकर सख्त नियंत्रण में लाना होगा। हर भवन का फायर ऑडिट और संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य होना चाहिए। बेसमेंट में कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। खिड़कियों पर लगी ग्रिलें रोकने का माध्यम बनने पर दंडनीय अपराध हों, और किसी भी मौत की स्थिति में प्रबंधन पर सीधे आपराधिक हत्या का मुकदमा चले। साथ ही एक स्वतंत्र ÷नेशनल कोचिंग सेफ्टी अथॉरिटी÷ बनाई जाए, जो राजनीतिक दबाव से मुक्त हो।

सुधार की सीमा केवल कोचिंग संस्थानों तक नहीं हो सकती। समस्या उस व्यापक शिक्षा ढांचे में छिपी है, जो छात्रों पर एकतरफा दबाव डालकर सफलता का सीमित रास्ता दिखाता है। जब सफलता का एकमात्र मानक प्रतियोगी परीक्षाएँ बन जाती हैं, तो कोचिंग उद्योग स्वतः ही अनियंत्रित बाजार में बदल जाता है। इसलिए स्कूलङ्कॉलेज स्तर पर सुधार, परीक्षा प्रणाली का संतुलन और मानसिक दबाव में कमी केवल शैक्षणिक सुधार नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जरूरी कदम हैं।

अगर अब भी यह चेतावनी अनसुनी रही, तो हर शहर किसी न किसी दिन लखनऊ की ही पुनरावृत्ति बन जाएगा। हर इमारत किसी अंधेरी रात में ÷लखनऊ आग में 15 जवान सपनों की राख÷ जैसी दर्दनाक कहानी दर्ज करती रहेगी। हम तब भी सिर्फ खबरें पढ़ेंगे, जांचें देखेंगे और अगले हादसे के आने का इंतजार करते रहेंगे। लेकिन उस समय शायद सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा–क्योंकि तब तक सपने, उम्मीदें और जीवन, सब कुछ पहले ही राख में बदल चुका होगा, और व्यवस्था केवल पछतावे के पन्ने पलटती रह जाएगी।

–प्रो. आरके जैन

चुनौतियों के साथ अवसरों का भी दौर

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। एक ओर खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर थोक महंगाई में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के भू-राजनीतिक तनावों में कमी के बाद रुपया फिर मजबूती की ओर बढ़ा है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह तस्वीर आश्वस्त करने वाली है, पर इसके भीतर कुछ ऐसे संकेत भी छिपे हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण संकेत थोक और खुदरा महंगाई के बीच बढ़ता अंतर है। हाल में थोक महंगाई तेजी से बढ़ी है, जबकि खुदरा महंगाई अपेक्षाकृत नियंत्रित रही है। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती। उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि का बोझ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचता ही है। इसलिए आज जो दबाव उद्योगों और उत्पादकों पर दिखाई दे रहा है, उसका असर आने वाले समय में आम उपभोक्ता की जेब पर भी पड़ सकता है।

थोक महंगाई मुख्यतः उन लागतों को दर्शाती है, जिनका सामना उत्पादकों को करना पड़ता है। जब ऊर्जा, परिवहन, आयातित कच्चे माल और विनिर्माण की लागत बढ़ती है, तब कंपनियां शुरुआत में अपने मुनाफे में कटौती करके कुछ बोझ स्वयं वहन करती हैं, पर यदि लागत का दबाव बना रहता है तो अंततः कीमतों में वृद्धि करनी पड़ती है। थोक महंगाई में हाल की तेजी को केवल एक अस्थायी घटना मानना उचित नहीं होगा। इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण ऊर्जा लागत है। वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईंधन और बिजली की ऊंची कीमतों ने उत्पादन लागत को बढ़ाया है। सकारात्मक पक्ष यह है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक तेल कीमतों में नरमी आई है। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए यह राहत के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर भी है।

अक्सर कम तेल कीमतों को अतिरिक्त खर्च करने का अवसर समझ लिया जाता है, पर यह दृष्टिकोण दूरदर्शी नहीं होगा। बाजारों के उतार-चढ़ाव स्थायी नहीं होते। समझदारी इसी में है कि अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने में किया जाए। सबसे पहले घटी तेल कीमतों से होने वाले लाभ का उपयोग बाहरी क्षेत्र की मजबूती के लिए किया जाना चाहिए। जब तेल आयात बिल घटता है तो चालू खाते का संतुलन बेहतर होता है। इस अवसर का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूत करने में किया जा सकता है। मजबूत भंडार केवल आर्थिक शक्ति का प्रतीक नहीं होते, बल्कि भविष्य के वैश्विक झटकों के खिलाफ सुरक्षा कवच भी प्रदान करते हैं। दूसरा, यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का उपयुक्त समय है। पिछले एक दशक में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रत्येक नई प्रगति भारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को कम करेगी।

–सुनील कुमार महला

लापरवाही की लपटों में जलती जिंदगी: कब जागेगा तंत्र?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग ने केवल एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता, नियामक संस्थाओं की निष्क्रियता और व्यवस्था की खोखली पड़ चुकी जवाबदेही को भी उजागर कर दिया है। इस दुर्घटना में कोचिंग सेंटर के अनेक विद्यार्थियों की असामयिक मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि उस सड़ी-गली व्यवस्था का परिणाम है, जो हर त्रासदी के बाद कुछ दिनों तक सक्रिय दिखती है और फिर गहरी नींद में सो जाती है। राजकोट के गेमिंग जोन में आग, दिल्ली के शिशु अस्पताल में नवजातों की मौत, दिल्ली के होटल अग्निकांड, मुजफ्फरपुर अस्पताल की दुर्घटना और अब लखनऊ का अग्निकांड-इन घटनाओं की श्रृंखला बताती है कि भारत में मानव जीवन का मूल्य लगातार घटता जा रहा है। हर बार वही बयान सुनाई देता है-'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा', 'जांच के आदेश दे दिए गए हैं', 'कड़ी कार्रवाई होगी'। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जांच और मुआवजा ही शासन का अंतिम दायित्व है? क्या सरकारें केवल दुर्घटना के बाद शोक व्यक्त करने और मुआवजा बांटने के लिए हैं? इन जहरीली काली आग ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। कितनी ही आंखों की रोशनी छीन ली और एक कालिख पोत दी कानून और व्यवस्था के कर्णधारों के मुँह पर।

लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी, वहां कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है कि क्या उस भवन को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त था? क्या भवन निर्माण मानकों का पालन किया गया था? क्या वहां आपातकालीन निकास मार्ग उपलब्ध थे? यदि थे, तो वे उपयोग में क्यों नहीं आए? और यदि नहीं थे, तो इतने लंबे समय तक प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? यह केवल भवन स्वामी की लापरवाही नहीं है। यदि कोई व्यावसायिक संस्थान नियमों की अनदेखी करते हुए वर्षों तक संचालित होता रहता है, तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र की मौन सहमति या भ्रष्ट गठजोड़ सक्रिय है। आखिर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? क्या उनका कार्य केवल लाइसेंस जारी करना और औपचारिक निरीक्षण करना भर रह गया है? या कमियों को ढंकते हुए अपनी जैबें गर्म करते रहना है?

वास्तविकता यह है कि देश के अधिकांश शहरों में सार्वजनिक सुरक्षा भगवान भरोसे है। ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं, लेकिन उनमें सुरक्षा मानकों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहुमंजिला भवनों में अक्सर एक ही प्रवेश एवं निकास मार्ग होता है। अग्निशमन उपकरण या तो अनुपस्थित होते हैं या वर्षों से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। आपदा प्रबंधन की कोई नियमित मॉक ड्रिल नहीं होती। भवनों में क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाता है। नियम पुस्तकों में सुरक्षा व्यवस्था भले मौजूद हो, लेकिन जमीन पर उसकी स्थिति नगण्य है। इस विडम्बना का सबसे दुखद पक्ष यह है कि हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच समितियां गठित होती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन उन रिपोर्टों पर अमल नहीं होता। उपहार सिनेमा अग्निकांड से लेकर राजकोट और लखनऊ तक, देश ने अनेक त्रासदियों से सबक लेने की बात कही, परंतु व्यवस्था ने कुछ नहीं सीखा। प्रशासन की स्मृति अत्यंत अल्पकालिक हो चुकी है। कुछ दिनों तक छापेमारी, निरीक्षण और नोटिस जारी करने का नाटक चलता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।

यह स्थिति केवल प्रशासनिक अक्षमता की नहीं, बल्कि नैतिक पतन की भी है। भ्रष्टाचार ने सुरक्षा व्यवस्था की आत्मा को खोखला कर दिया है। निरीक्षण करने वाले अधिकारी सुविधा शुल्क लेकर आंखें मूंद लेते हैं। भवन स्वामी अधिक लाभ कमाने के लिए सुरक्षा उपायों की उपेक्षा करते हैं। परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवाते हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या हमारे शहरों का विकास मानव-केंद्रित है? हम स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी और विश्वस्तरीय शहरों के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन यदि नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे विकास का क्या अर्थ है? किसी भी सभ्य समाज की पहली पहचान उसके नागरिकों की सुरक्षा होती है। यदि एक कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल या मॉल भी सुरक्षित नहीं है, तो हमें अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार करना होगा। आज आवश्यकता केवल दोष निर्धारण की नहीं, बल्कि व्यापक संरचनात्मक सुधारों की है। सबसे पहले देशभर में सभी व्यावसायिक भवनों, कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, मॉल, होटल और सार्वजनिक स्थलों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए। जिन संस्थानों के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं हैं या जो मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

दूसरे, अग्निशमन विभाग को आधुनिक संसाधनों और पर्याप्त मानवबल से सुसज्जित करना होगा। अनेक रिपोर्टों के अनुसार देश में फायर स्टेशनों और प्रशिक्षित फायर कर्मियों की भारी कमी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के अनुरूप अग्निशमन सेवाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। तीसरे, प्रत्येक सार्वजनिक भवन में हर छह माह में अनिवार्य मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आपात स्थिति में लोग घबराने के बजाय संयमपूर्वक अपनी सुरक्षा कर सकें। चौथे, जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। केवल भवन स्वामी ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागों के उन अधिकारियों पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने लापरवाही बरती या नियमों की अनदेखी की। जब तक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाए जाएंगे, तब तक सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन की प्राथमिकता 'दुर्घटना के बाद की प्रतिक्रिया' से बदलकर 'दुर्घटना से पूर्व की रोकथाम' पर केंद्रित होनी चाहिए। सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना भी है। प्रशासन की सफलता मुआवजा राशि में नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने की क्षमता में निहित होती है।

कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, कारखाने, होटल आदि के मिस मैनेजमेंट और लापरवाही का स्थानीय प्रशासन को अंदाजा होना चाहिए कि उसके कार्यक्षेत्र में किस तरह के व्यवसाय कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए चलाए जा रहे हैं? प्रश्न है कि इन बढ़ती दुर्घटनाओं की नृशंस चुनौतियों का क्या अंत है? बहुत कठिन है दुर्घटनाओं की उफनती नदी में जीवनरूपी नौका को सही दिशा में ले चलना और मुकाम तक पहुंचाना, यह चुनौती सरकार के सम्मुख तो है ही, आम जनता भी इससे बच नहीं सकती। मनुष्य अपने स्वार्थ और रुपए के लिए इस सीमा तक बेईमान और बदमाश हो जाता है कि हजारों के जीवन और सुरक्षा से खेलता है। दो-चार परिवारों की सुख समृद्धि के लिए अनेक घर-परिवार उजाड़ देता है। तंत्र की काहिली और आपराधिक लापरवाही के चलत ऐसे हादसे होते हैं जिनमें भ्रष्टाचार पसरा होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे-कानूनों का उल्लंघन होता है। आखिर क्या वजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती है? सारे कानून कायदों का वहीं पर स्याह हनन होता है।

जैसे-जैसे जीवन तेज़ होता जा रहा है, सुरक्षा उतनी ही कम हो रही है, जैसे-जैसे प्रशासनिक सर्तकता की बात सुनाई देती है, वैसे-वैसे प्रशासनिक कोताही के सबूत सामने आते हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हर बड़ी दुर्घटना कुछ शोर-शराबें के बाद एक और नई दुर्घटना की बाट जोहने लगती है। सरकार और सरकारी विभाग जितनी तत्परता मुआवजा देने में और जांच समिति बनाने में दिखाते हैं, अगर सुरक्षा प्रबंधों में इतनी तत्परता दिखाएं तो दुर्घटनाओं की संख्या घट सकती है। लखनऊ का यह अग्निकांड एक चेतावनी है। यदि अब भी शासन-प्रशासन नहीं जागा, तो ऐसी त्रासदियां भविष्य में और अधिक भयावह रूप धारण कर सकती हैं। यह समय आत्ममंथन का है, क्योंकि हर अग्निकांड के बाद यदि केवल राख बचती है और व्यवस्था फिर उसी ढर्रे पर लौट जाती है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि एक प्रकार का संस्थागत अपराध है। देश को अब संवेदना नहीं-व्यवस्था चाहिए, जांच नहीं-जवाबदेही चाहिए और आश्वासन नहीं-ठोस कार्रवाई चाहिए। अन्यथा हर अग्निकांड के बाद यही प्रश्न गूंजता रहेगा-आखिर कब जागेगा तंत्र?

–ललित गर्ग

29 साल बाद भी दिल्ली ने अग्निकांडों के दर्दनाक हादसों से नहीं लिया सबक

दिल्ली में जून के महीने में हुई भीषण आग की दो घटनाओं में एक अजीब समानता है। 13 जून, 1997 को ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा हॉल अ?ग्निकांड में 59 लोग दम घुटने से मर गए। इस सिनेमा हॉल में मुनाफे के लिए गैर-कानूनी तौर पर बदलाव किए गए थे। वहीं, 3 जून, 2026 को कुछ ही किलोमीटर दूर हौज रानी में, फ्लरिश स्टे बेड-ऐंड-ब्रेकफास्ट में 21 लोगों की मौत हो गई।

इस इमारत में सिर्फ छह कमरों की अनुमति के बावजूद 26 कमरे चल रहे थे और इसे अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं था। इन दोनों त्रासदियों के बीच 29 साल का अंतर है, फिर भी इनसे मिलने वाले सबक कहीं नजर नहीं आते। यह समानता मेरे लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। मेरी बुआ रेखा मेहरा, और मेरे रिश्ते के भाई वेदांत मेहरा, उपहार सिनेमा हॉल में मरने वाले 59 लोगों में शामिल थे, और इस जून में यह दुख ऐसे लौट आया मानो इतने साल बीते ही न हों।

हौज रानी में मारे गए लोग शहर की छिपी हुई अर्थव्यवस्था की एक झलक थे- कामगार और ऐसे मरीज जो इलाज के लिए महाद्वीप पार करके आए थे क्योंकि उनके अपने देश में इलाज का खर्च वहन करना संभव नहीं था। मृतकों में से 11 विदेशी नागरिक थे। इसके बाद की प्रशासनिक प्रक्रिया जानी-पहचानी सी रही। एक रसोइये को हिरासत में लिया गया, मालिक को गिरफ्तार किया गया और अनधिकृत अतिथि गृहों पर कार्रवाई की घोषणा की गई। सजा देने में जो दक्षता होती है, वह रोकथाम में नहीं दिखती, जो भ्रष्टाचार से लथपथ अफसरशाही की दलदल में दबी पड़ी है।

इस आग से जुड़ा सबसे कठिन सवाल यह है कि भारत में विकास और शहरीकरण का क्या अर्थ है। हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित कर ली है जो आईफोन से लेकर बिरयानी तक सब कुछ 10 मिनट में घर तक पहुंचा सकती है, लेकिन एक गली के जरिये दमकल गाड़ी को 20 मिनट में नहीं पहुंचा सकती।

आज हमारे शहरीकरण का अधिकांश हिस्सा अधिकतम किराये के लिए जमीन हथियाने, तय सीमा से अधिक ऊंची इमारतें बनाने और अस्पतालों का इस बात की परवाह किए बिना विस्तार करने से जुड़ा है कि वहां आने वाले मरीजों के सोने की व्यवस्था कहां होगी। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विकास को मापना प्रगति माना जा सकता है, लेकिन यह पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है।

यह सिर्फ आग लगने की घटना नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी ढांचे की विफलता एक आम समस्या है। जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाढ़ग्रस्त बेसमेंट में तीन सिविल सेवा अभ्य?र्थियों की डूबने से मौत हो गई, जबकि वहां पुस्तकालय होना ही नहीं चाहिए था। इसी साल फरवरी में जनकपुरी में कमल ध्यानी अपनी मोटरसाइकल लेकर जल बोर्ड के एक ऐसे 14 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरे, जिस पर कोई निशान या चेतावनी नहीं लगी थी।

एक अनुमान के अनुसार, 2019 से राजधानी में आग लगने की घटनाओं में 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। समाजशास्त्री चार्ल्स पेरो ने उत्पन्न आपदाओं का वर्णन करने के लिए 'सामान्य दुर्घटनाएं' शब्द का प्रयोग किया, जो किसी व्यक्ति की गलती के बजाय जटिल सिस्टम की वजह से होती हैं।

हमारे शहरों ने इस अवधारणा को और भी पुख्ता किया है- ये मौतें सामान्य हैं, दुर्घटनाएं नहीं। ये उन फैसलों का नतीजा हैं जो लिए गए, टाले गए या जिनसे पैसे कमाने की कोशिश की गई। देश में ऐसे स्थान क्यों मौजूद हैं? भारत के टियर-1 शहरों में, अनौपचारिकता शायद ही कभी नियोजन की कमी होती है, बल्कि यह स्वयं नियोजन का एक तरीका है।

ये स्थान इसलिए बनते और सहन किए जाते हैं क्योंकि ये उपयोगी हैं। हर अस्पताल, मॉल और ऑफिस टावर सस्ते कमरों और लचीले श्रम की मांग पैदा करता है, जो किसी स्वीकृत योजना में उपलब्ध नहीं होते, इसलिए अनधिकृत बस्तियां इनकी पूर्ति करती हैं। जिसे हम अवैध निर्माण कहते हैं, वह शहर द्वारा अपनी आवास समस्या को गरीबों पर थोपने जैसा है। हौज रानी के गेस्ट हाउस नियोजन की अवहेलना करते हुए नहीं बने, वे इसलिए बने क्योंकि नियोजन ने एक खालीपन छोड़ दिया और किराये ने उसे भर दिया।

किसी शहर की प्रगति का एक उचित मापदंड यह है कि वह अपने सबसे कमजोर निवासियों को कितने अच्छे विकल्प प्रदान करता है। इस मापदंड के अनुसार, एक महानगर जो किफायती आवास और सुरक्षित आवास के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है, वह विकसित नहीं हो रहा है, बल्कि केवल विस्तार कर रहा है। संस्थागत भ्रष्टाचार के नीचे एक ऐसी चीज छिपी है जिसके खिलाफ कानून बनाना कहीं अधिक कठिन है, एक नैतिक पतन जो रोजमर्रा के नागरिक जीवन में समा चुका है। यह नागरिकों के रूप में हमारी चुप्पी में भी झलकता है।

हममें से कुछ ही लोग यह सोचने के लिए रुकते हैं कि जिस इमारत में हम सोते हैं उसे किसने मंजूरी दी थी या उसका आपातकालीन निकास कहां जाता है। हम, भारत के नागरिक सवाल पूछना और जीवन की उस गुणवत्ता पर जोर देना भूल गए हैं जो मायने रखती है।

हमने मात्रा को ही प्राथमिकता दी है, ज्यादा मंजिलें, ज्यादा वर्ग फुट, तेज डिलिवरी, जबकि एक सुरक्षित कमरा या पैदल चलने योग्य सड़क जैसी बुनियादी गरिमा हमारी सामूहिक कल्पना से ओझल हो गई है। जो समाज बेहतर की मांग नहीं करता, उस पर निश्चित रूप से वही लोग शासन करेंगे जो उसे प्रदान नहीं करते। अंततः, यह नैतिकता का मामला है, जो हर स्तर पर खो गई है।

उपहार के पीड़ितों के परिवार, जिनमें मेरा परिवार भी शामिल है, उन्होंने अगली आगजनी को रोकने के लिए दो दशकों से अधिक समय अदालतों में बिताया। फिर भी, उसी महीने, उसी शहर में, उन लोगों के साथ आगजनी हुई जिनके पास जवाब मांगने की शक्ति और भी कम थी।

–धनंजय राजौरा

फोरलेन निर्माण में गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल

नाले के निर्माण के दौरान भी गुणवत्ता का नहीं रखा जा रहा ध्यान, गत दिवस ट्रैक्टर चढ़ने से टूट गई थी नाले की स्लैब

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहरी हाइवे का निर्माण जारी है। इस दौरान फोरलेन के दोनों ओर नगरीय सीमा में नाले का निर्माण किया जा रहा है। इस नाले के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे है, क्योंकि दो दिन पहले नाले की स्लैब से ट्रेक्टर निकलते समय स्लैब टूट गई थी। इधर फोरलेन निर्माण में भी लगातार गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे है, हालांकि अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य सही हो रहा है। ऐसे में यदि वास्तविकता के आधार पर सही जांच की जाए तो कई खामियां सामने आ सकती है।

शहरी हाइवे को फोरलेन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा 84.71 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूरे नगर के बीच से निकली जिला मुख्य सडक़ के 10 किमी मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए निर्माण जारी है। जिससे यहां पर यातायात का दबाव कम होगा। निर्माण एजेंसी द्वारा साइड क्लियरेंस के बाद निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगर में चिह्नित स्थानों पर निर्माण एजेंसी द्वारा सीसी नालों का निर्माण किया जा रहा है। बताया गया कि इस नाले का निर्माण पूरे फोरलेन पर नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार जिन स्थानों पर जल निकासी को लेकर परेशानी आ सकती है वहां पर नालों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि नाले के निर्माण को लेकर लगातार परेशानियां सामने आ रही है। कई स्थानों पर नाले की दीवार ज्यादा ऊंची उठाने से इसके आसपास के दुकानदारों को आने-जाने में भी परेशानी हो रही है। दूसरी और नाले के निर्माण में भी लापरवाही बरती जा रही है। 5 जून को ही धोबी चौराहा स्थित महिंद्रा शोरूम के पास नवनिर्मित नाले के स्लैब से एक ट्रैक्टर-ट्राली के गुजरते ही सीमेंट कांक्रीट की स्लैब टूटकर गिर गई थी। ऐसे में लोगों का कहना था कि निर्माण कार्य इतने निम्न स्तर का है कि अभी निर्माण जारी ही है और स्लैब टूटने लगी है। ऐसे में आने वाले समय में क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

चार इंच की जगह, 8 इंच पर लगाए जा रहे सरिये- बताया गया कि नाला निर्माण में खासी लापरवाही बरती जा रही है। जानकारों के अनुसार नाले के निर्माण में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसमें दीवार का निर्माण करने के बाद उसमें सरिये लगाने की भी जानकारी सामने आई थी। वहीं निर्माण में जो चार इंच की गेप में सरिये लगाए जाना था उसके स्थान पर 6-8 इंच पर सरिये लगाए जा रहे है। इसकी भी जांच नहीं होने के कारण ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। जबकि जिम्मेदार बगैर जांच के इस कार्य को भी गुणवत्ता का कार्य बता रहे है।

अंडर वेट लगाए जा रहे विद्युत पोल- शहरी हाइवे के फोरलेन निर्माण के दौरान विद्युत लाइन की शिफ्टिंग भी की जा रही है। इस शिफ्टिंग के कार्य में जमकर लापरवाही हो रही है। यहां पर लगाए जाने वाले नए विद्युत पोल अंडर वेट लगाए जा रहे है। तय मानक के हिसाब से विद्युत पोल अंडर वेट है। खास बात यह है कि मक्सी क्षेत्र में भी फोरलेन निर्माण में इसी तरह के अंडरवेट विद्युत पोल लगाए जा रहे है। यदि इसकी नियमानुसार जांच की जाए तो ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आ सकती है।

इनका कहना है- जिस स्थान पर स्लैब धंसी थी वहां पर एप्रोच का काम चल रहा था और वहां पर पाइप नहीं डाल पाए थे। इसके कारण परेशानी आई थी, अब कोई परेशानी नहीं है। निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाता है। लैब में टेस्टिंग भी हो रही है। विद्युत पोल अंडरवेट के संबंध में जानकारी नहीं है।

- हर्षवर्द्धनसिंह मुवेल, ईई, पीडब्ल्यूडी-शाजापुर

आगे चल रहे ट्रक में घुसा दूसरा ट्रक, चालक की मौत

उकावता चौकी के पास हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। नेशनल हाईवे-52 पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। उकावता पुलिस चौकी क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के पास ब्रेकर पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने आगे चल रहे दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार पीछे वाले ट्रक के चालक को नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण वह नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाले ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिस ट्रक को टक्कर मारी गई थी उसका चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। यह हादसा सोमवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुआ। घटना की सूचना मिलते ही उकावता पुलिस चौकी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे चालक और हेल्पर को बाहर निकाला। लेकिन तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। घायल हेल्पर को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। उकावता चौकी प्रभारी रमेश यादव ने बताया कि मृतक चालक की पहचान कानपुर निवासी गुलाबचंद पिता गुरुप्रसाद गुप्ता के रूप में हुई है। घायल हेल्पर का नाम विनोद है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

कृत्रिम पैरों से अरविंद के आत्मविश्वास और सपनों को मिली नई उड़ान

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। शासन द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र कल्याण और उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक है ÷एडिप योजना÷, जो दिव्यांगजनों के जीवन में नई रोशनी और आत्मविश्वास का संचार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों को समय पर आवश्यक सहायता मिल रही है। सीहोर जिले के ग्राम मेमदाखेड़ी निवासी श्री अरविंद सिंह के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जब उन्हें जानकारी मिली कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सीहोर में विशेष शिविर आयोजित कर दिव्यांगजनों को ऑन द स्पॉट कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वे निर्धारित समय पर शिविर में पहुंचे। शिविर में उनका पंजीयन किया गया और विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण उपरांत उन्हें वहीं निशुल्क कृत्रिम पैर प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें उपयोग में सुविधा के लिए आरामदायक जूते भी निःशुल्क उपलब्ध कराए गए।

कृत्रिम पैर प्राप्त करने के बाद श्री अरविंद सिंह के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि अब वे पहले की अपेक्षा अधिक सहजता से अपने दैनिक कार्य कर सकेंगे और आत्मनिर्भर जीवन जी पाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई है। एडिप योजना के माध्यम से शासन न केवल दिव्यांगजनों को सहारा दे रहा है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके जीवन को नई दिशा दे रहा है। ऐसे प्रयास यह सिद्ध करते हैं कि सरकार संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचकर उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

नगर में निकला तहसील के दुलदुल बाबा का पारंपरिक जुलूस

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। मोहर्रम के मौके पर देर रात तहसील के दुलदुल बाबा का ऐतिहासिक जुलूस पूरी अकीदत और शांतिपूर्वक माहौल में निकाला गया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग ने शिरकत की शहर मोहर्रम कमेटी मीडिया प्रभारी सय्यद आफ़ताब अली ने बताया कि जुलूस की शुरुआत लालपुरा से हुई। इसके बाद जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों मगरिया, सोमवारिया बाजार होते हुए बड़े चौक पहुंचा।

बड़े चौक में समाज के लोगों द्वारा सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दुलदुल बाबा की दौड़ भी लगाई गई। यह जुलूस जुलूस-ए-सदर सम्मी भाई की सदारत में पूरी तरह शांतिपूर्वक निकाला गया। जब जुलूस चौक में पहुंचा तो सालों से चली आ रही सफा बांधने की रस्म अदा की गई शहर मोहर्रम कमेटी अध्यक्ष इमरान खरखरे और उनकी पूरी टीम को इस मौके पर सफा बांधकर सम्मानित किया गया। शहर मोहर्रम कमेटी अध्यक्ष इमरान खरखरे ने कहा कि नगर में सभी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जा रहे हैं और आगे भी हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के साथ मनाए जाएंगे। उन्होंने सभी से अपील की कि सभी लोग मोहर्रम पर्व को मिलजुल कर मनाएं। कार्यक्रम में शहर मोहर्रम कमेटी के सदर इमरान खरखरे, सलीम भाई ठेकेदार, अकरम भाई खजांची, सबदर भाई, सौरभ भाई, जुलूस के सदर सम्मी भाई आदि उपस्थित थे।

हवा में तो उड़ गई छत, बारिश के मौसम में हो जाएगा हादसा

पीएम आवास के लिए तीसरी बार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताई परेशानी

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। तेज आंधी और हवा से हमारे कच्चे मकानों पर लगी चद्दरें कई बार उड़ गई, बारिश में कभी भी हमारे मकान हादसे का कारण बन सकते हैं। इससे पहले हमें प्रधानमंत्री आवास प्रदान कर दीजिए। यह कहना था ग्राम आरोलिया के ग्रामीणों का, जो तीसरी बार जनसुनवाई में पहुंचे थे।

ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। उनका कहना है कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं फिर भी उन्हें अब तक किसी भी सरकारी आवासीय योजना का फायदा नहीं मिला है। हम लोग लंबे समय से कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। गांव के कई परिवारों के पास तो शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण वे खुद का पक्का मकान बनाने में पूरी तरह असमर्थ हैं और मजदूरी करके जैसे-तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। फिर भी हम सभी की अनदेखी की जा रही है।

9 सालों से काट रहे कलेक्टर कार्यालय के चक्कर- ग्रामीणों ने भेदभाव का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि गांव के कई अन्य लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिल चुके हैं, लेकिन पात्रता होने के बावजूद उन्हें इस सूची से बाहर रखा गया है। ग्रामीण वर्ष 2018 से ही लगातार इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि अपनी इस मांग को लेकर वे तीसरी बार कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही उनकी चिंता और बढ़ गई है क्योंकि तेज हवा-आंधी में उनके कच्चे मकानों की चद्दरें उड़ जाती हैं, जिससे परिवार पर हर वक्त किसी हादसे का खतरा मंडराता रहता है।

निरीक्षण करें तो पता चलेगी वास्तविकता- परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि अधिकारी मौके पर आकर जमीनी हकीकत का निरीक्षण करें। तब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग किस तरह अपना जीवन मुश्किलों में जी रहे हैं। बारिश के दिनों में हमारे साथ कीभी भी कोई हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने मांग की कि जल्द से जल्द उनके लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराएं।

प्रेमी के साथ रह रही विवाहिता को पति ने साथियों संग कथित रूप से उठाया, विरोध करने पर पिता-पुत्र पर हमला

20 घंटे बाद दर्ज हुई एफआईआर, महिला और आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को कथित रूप से जबरन अपने साथ ले जाने और उसके साथ रह रहे युवक व उसके पिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के करीब 20 घंटे बाद पुलिस ने महिला के पति, जेठ, काका ससुर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक महिला का कोई पता नहीं चल सका था, वहीं आरोपी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रहलाद पिता चुन्नीलाल बावरी निवासी पिपलियामंडी ने मल्हारगढ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्रवधू नहीं बल्कि उसका पुत्र दीपक बावरी पिछले करीब छह माह से मंजूबाई के साथ रह रहा था। मंजूबाई का विवाह अनिल मीणा निवासी फोफलिया थाना जीरन जिला नीमच से हुआ था। बताया गया है कि मंजूबाई अपनी इच्छा से दीपक के साथ रह रही थी तथा दोनों ने न्यायालय में संरक्षण संबंधी दस्तावेज भी तैयार करवाए थे।

रिपोर्ट के अनुसार 21 जून की शाम करीब 7 बजे मंजूबाई, दीपक बावरी, साजिद मंसूरी एवं आरिफ के साथ ग्राम रूपी से मजदूरी कर पिपलियामंडी लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम सोनी-रूपी मार्ग स्थित भगवती वेयरहाउस के पास अनिल मीणा अपने बड़े भाई शांतिलाल, काका लखमीचंद रावत तथा अन्य साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आरोप है कि अनिल और उसके साथियों ने रास्ता रोककर दीपक बावरी पर बियर की बोतलों और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर में चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचे प्रहलाद बावरी के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उन्हें भी चोटें आईं। इसके बाद आरोपियों ने मंजूबाई को कथित रूप से जबरन वाहन में बैठाया और अपने साथ ले गए।नघटना के बाद घायल दीपक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष ने इसे जबरन अपहरण और जानलेवा हमला बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले में मल्हारगढ़ पुलिस ने अनिल मीणा, शांतिलाल मीणा, लखमीचंद रावत सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

सूत्रों के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद और वैवाहिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में महिला के मिलने और उसके बयान दर्ज होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह अपनी इच्छा से पति के साथ गई है या उसे जबरन ले जाया गया था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अनिल मीणा की पत्नी मंजूबाई अपनी इच्छा से दीपक बावरी नामक युवक के साथ रह रही थी। इसी बात से नाराज होकर अनिल अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचा और कथित रूप से पत्नी को अपने साथ ले गया। साथ ही दीपक और उसके पिता के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। महिला का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और उसकी तलाश की जा रही है। महिला के बयान के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा पुलिस आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

भेरू महाराज की प्रतिमा और दुकानों पर मिले थूक के निशान

मोहर्रम के जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने की हरकत से नगरवासी हुए नाराज

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। मुस्लिम समाज के 10 दिनी मातमी पर्व के दौरान नगर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। सोमवार रात को भी दुलदुल बाबा का जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने भेरू महाराज की प्रतिमा सहित कुछ लोगों की दुकान पर थूक दिया। सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और पुलिस से इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

सोमवारिया बाजार स्थित भेरू महाराज की प्रतिमा पर जब आसपास के दुकानदार पूजन करने पहुंचे तो उनकी नजर वहां लगे थूक के निशान पर पड़ी। इसके बाद कुछ व्यापारियों की दुकानों पर भी पाउच की पिक मिली। इससे नगरवासी नाराज हो गए। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रतिमा को पानी से साफ कराया और उसका दोबारा श्रृंगार किया। मंदिर के आसपास की कुछ दुकानों और होटल के बाहर भी थूक के निशान मिले हैं, जिससे व्यापारियों में गहरी नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों को भी प्रतिमा के आसपास थूक के निशान मिले हैं। लोगों ने बताया कि शहर में इन दिनों मोहर्रम पर्व के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम निकल रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि किसी शरारती तत्व ने माहौल खराब करने के उद्देश्य से यह हरकत की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि मोहर्रम के दौरान निकलने वाले सभी जुलूसों के आयोजकों को समझाइश दी जाएगी और मंदिर क्षेत्र में जुलूस के समय अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।

छत से घुसे बदमाश ने घर ले जाकर किया नाबालिग से दुष्कर्म

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के मक्सी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ने नाबालिग को उसकी पुरानी तस्वीरें दिखाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस को दिए बयान में नाबालिग ने बताया कि वह आरोपी अल्तमस को करीब दो वर्षों से जानती है। पीड़िता के अनुसार 17 जून की दोपहर करीब एक बजे वह आरोपी की मां के बुलाने पर उनके घर मेहंदी लगाने गई थी। काम खत्म होने के बाद जब वह घर लौटने लगी तभी अल्तमस ने उसे रोक लिया। उसने पीड़िता को मोबाइल में उसकी सामान्य तस्वीरें दिखाते हुए पूछा कि वह उससे फोन पर बात क्यों नहीं करती। जब पीड़िता ने बात करने से इनकार किया तो आरोपी ने उसकी तस्वीरें एडिट कर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि धमकी के डर से उसने एक-दो बार आरोपी से फोन पर बात की। इसके बाद 21 और 22 जून की दरमियानी रात करीब दो बजे आरोपी उसके घर की छत के रास्ते कमरे में घुस गया। उस समय पीड़िता अपनी छोटी बहन और भाई के साथ सो रही थी। आरोपी ने उसका मुंह दबाया और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसे जबरन अपने घर ले गया। वहां उसने अपने कमरे में नाबालिग के साथ रेप किया। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसके गले पर काट लिया और जान से मारने की धमकी भी दी। करीब एक-दो घंटे बाद जब परिजन उसकी तलाश करते हुए आरोपी के घर पहुंचे तो अल्तमस ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इसी दौरान पीड़िता का भाई घर के पीछे बने बाड़े तक पहुंचा, जहां नाबालिग छिपी हुई मिली। इसके बाद वह उसे अपने साथ घर लेकर आया। घर पहुंचने पर नाबालिग ने पूरी घटना परिजनों को बताई, जिसके बाद उसे लेकर मक्सी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

साइबर सेल की सहायता से 24 घंटे में बरामद हुई अपहृत नाबालिग

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड।अपने घर से लापता हुई एक नाबालिग को मोहन बड़ोदिया पुलिस ने 24 घंटे में बरामद कर लिया। यह सफलता पुलिस ने साईबर सेल की सहायता से मिली। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

सोमवार को फरियादी ने मोहन बड़ोदिया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 15 वर्षीय बेटी बिना बताए कहीं चली गई है। फरियादी ने आशंका जताई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने इस पर धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी यशपालसिंह राजपूत ने भी नाबालिग की बरामदगी के लिए पांच हजार रुपए के इनाम की घोषणा की थी। इसके बाद पुलिस ने भी परिजनों, संदेहियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए। वहीं मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया जिनकी सूचना पर पुलिस ने आगर जिले के ग्राम झारला से नाबालिग को सकुशल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी कमल मालवीय निवासी अरनिया और अरमान निवासी कानड को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वैन को भी जब्त किया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी अरविंदसिंह तोमर, उनि. कैलाशनारायण यादव, प्रधान आरक्षक मो. शरीफ, प्रधान आरक्षक रविशंकर चौधरी, आरक्षक राहुल जाट, चालक आरक्षक विष्णु प्रसाद दांगी, आरक्षक अर्जुन बागड़ी, महिला आरक्षक राधिका राजपूत तथा साइबर सेल प्रभारी विकास तिवारी एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राहवीर योजना अंतर्गत मिलेंगे 25 हजार रूपये

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ''राहवीर योजना अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के तहत सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति अस्पताल तक पहुंचाता है तो उसे पुलिस द्वारा अनावश्यक पूछताछ नहीं की जायेगी। शासन की राहवीर योजना अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसने किसी मोटर वाहन से जुड़ी गम्भीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर चिकित्सा सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर उपचार प्रदान करने के लिये अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो वह इस योजना के लिये पात्र होगा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गोल्डन ऑवर'' का अर्थ है किसी दर्दनाक चोट के बाद एक घंटे तक चलने वाली वह अवधि, जिसके दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है।

राजस्व कार्यों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, हितग्राही न हों परेशान - कलेक्टर

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित राजस्व कार्यों, लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, भू-अर्जन, किसान हित से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी मोहर्रम पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाऐ रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार गंभीरता से निराकरण किया जाए तथा आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण करना प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाएं, जिले को प्रदेश की रैंकिंग में शीर्ष 10 जिलों में बनाए रखे तथा नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। उन्होंने राजस्व कार्यों को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

महेश नवमी पर्व हर्षोल्लास एवं धार्मिक आस्था के साथ मनाया

बड़ावदा/ प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। माहेश्वरी समाज बड़ावदा द्वारा भगवान महेश (शिव) एवं माता पार्वती को समर्पित महेश नवमी पर्व मंगलवार को अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे दिन चले धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के सभी वर्गों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल प्रभात फेरी से हुई। समाज के महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर नगर के प्रमुख मार्गों पर प्रभात फेरी निकाली। भगवान महेश के जयकारों एवं भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके पश्चात माहेश्वरी रांगोला मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें समाजजनों ने भगवान से सुख, समृद्धि एवं समाज की उन्नति की कामना की।

महेश नवमी पर्व के अवसर पर समाजजनों ने सेवा भावना का परिचय देते हुए स्थानीय गौशाला पहुंचकर गौमाता को खली एवं हरा चारा खिलाया तथा गौसेवा का पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस दौरान समाज के वरिष्ठजनों ने गौसेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा बताया।

पर्व के अंतर्गत बच्चों एवं युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेता प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया।

इसके पश्चात सभी समाजजनों का सामूहिक सहभोज आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सभी परिवार एक साथ शामिल हुए। सहभोज के माध्यम से समाज में एकता, सौहार्द एवं पारिवारिक भावना को और अधिक मजबूती मिली।

महेश नवमी पर्व के सफल आयोजन में माहेश्वरी युवा संगठन, महिला मंडल एवं समाज के सभी वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि महेश नवमी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि समाज को संगठित करने, संस्कारों को आगे बढ़ाने और सेवा भाव को मजबूत करने का भी संदेश देती है। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, उत्साह एवं सामाजिक समरसता का वातावरण देखने को मिला।

मोहर्रम पर्व को लेकर एसपी अमित कुमार अलर्ट, आलोट ताजिया रूट एवं थाने का किया आकस्मिक निरीक्षण

आलोट/ राकेश चौहान/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रतलाम जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आलोट पहुंचकर ताजिया रूट का निरीक्षण किया तथा नगर के संवेदनशील क्षेत्रों एवं प्रमुख मार्गों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि मोहर्रम पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रहे, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए तथा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ताजिया मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, यातायात नियंत्रण एवं भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने आलोट थाना का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान लंबित अपराधों, फरार आरोपियों एवं स्थाई वारंटियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। एसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के हवालात, रिकॉर्ड रूम, शस्त्रागार, मालखाना एवं ड्यूटी रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों की जांच की। साथ ही ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यप्रणाली की जानकारी लेते हुए एफआईआर, शिकायतों एवं विभिन्न रजिस्टरों का भी अवलोकन किया।

इस दौरान ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल, जावरा एसडीओपी संदीप कुमार मालवीय, आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर, आलोट थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम एवं ताल थाना प्रभारी स्वराज सिंह डाबी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस प्रशासन की इस सक्रियता को देखते हुए आमजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विश्वास बढ़ा है।

बीच सड़क कार खड़ी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने काटा 500 का चालान

एसबीआई चौराहे पर यातायात बाधित करने पर वाहन चालक पर कार्रवाई

सुसनेर/ गिरिराज बंजारिया/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार को नगर के व्यस्त शुक्रवारिया बाजार स्थित एसबीआई बैंक चौराहे पर बीच सड़क पर खड़ी एक कार के कारण काफी देर तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। मुख्य मार्ग पर कर्नाटक पासिंग की कार खड़ी होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी समय तक वाहन के पास कोई नहीं पहुंचने पर लोगों ने कार को लावारिस समझते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार की जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा वाहन की जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पता चला कि कार के मालिक दिनेश पाटीदार हैं, जबकि वाहन कन्हैयालाल पाटीदार चला रहे थे। चालक बैंक के कार्य से एसबीआई शाखा में गए थे और उन्होंने कार को मुख्य सड़क पर ही खड़ा कर दिया था, जिससे चौराहे पर यातायात बाधित होने लगा।

मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले यातायात को सुचारु कराया, इसके बाद वाहन को अपने कब्जे में लेकर थाना परिसर पहुंचाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने और सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़ा कर आवागमन में बाधा उत्पन्न करने के मामले में चालक के विरुद्ध 500 का चालान काटकर वैधानिक कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चालक को समझाइश भी दी कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में वाहन को मुख्य सड़क या चौराहे पर खड़ा न करें। बैंक, बाजार अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने वाले वाहन चालक निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करना यातायात नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश भी मिला है।

माहेश्वरी समाज ने धूमधाम सै मनाया वंशोत्पति दिवस

अकोदिया/ अमर सिंह मेवाडा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार को स्थानीय माहेश्वरी समाज द्वारा समाज का वंशोत्पति दिवस महेश नवमी पर्व धूमधाम सै मनाया गया। सुबह 9 बजे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर सै समाजजनो द्वारा प्रभातफेरी निकाली गई।

प्रभारफेरी श्री हनुमान मंदिर, वैध गली, साईनाथ प्रिंटर्स चौराहा, सिद्धि विनायक चौराहा, झंडा चौक, शिवाजी मार्केट, टप्पा चौराहा होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। प्रभातफेरी मे उपस्थित समाजजन का गोपाल लाहोटी एवं माधव माहेश्वरी द्वारा निज निवास पर स्वागत किया गया। मंदिर पर पंडित दिलीप आंनद जी व पंडित अमित आनंद की उपस्थिति मे समाजजनो द्वारा भगवान शिव परिवार का विधि विधान सै अभिषेक किया गया।

इसके पश्चात महेश वंदना का गायन रीता लाहोटी सरिता राठी,ज्योति राठी, शशि सर्राफ द्वारा किया गया। महिलाओं के द्वारा लक्की गेम खेला गया उसमें प्रथम स्थान शशि सर्राफ,द्वितीय स्थान रेनू माहेश्वरी, तृतीय स्थान रीता लाहोटी ने प्राप्त किया। बच्चों के द्वारा चेयर रेस खेली गई प्रथम प्रजनन माहेश्वरी, सेकेण्ड मानवीक माहेश्वरी,तृतीय सौम्या माहेश्वरी रहै जिनको पुरस्कृत किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम मे जिलाध्यक्ष अजय राठी एवं महिला मंडल द्वारा 10वी में धैर्य सोमानी,12वी में शुभ राठी एवं सीए उत्तीर्ण करने पर श्रेयांश लाहोटी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मे जगन्नाथ चांडक,नटवरलाल राठी, अशोक लाहोटी,माधव माहेश्वरी, गोपाल राठी,दामोदर चांडक पोलाय,माहेश्वरी समाज नगर अध्यक्ष अनिल लाहोटी, सचिव पंकज सोमानी, गोपाल लाहोटी,राधाकिशन चांडक, रामेश्वर राठी,विजय सर्राफ,गोपाल माहेश्वरी पोलाय,सुरेंद्र राठी,कन्हैया राठी, प्रमोद लाहोटी,गोविन्द राठी,अजय सर्राफ,मनोहर राठी,सुनील लाहोटी,घनश्याम राठी,संजय राठी,राजू लाहोटी,निलेश राठी,संजय सोमानी,नरेंद्र चांडक,रवि सर्राफ,सम्पत माहेश्वरी,मोहित माहेश्वरी, शशांक लाहोटी, मयंक माहेश्वरी,मृदुल राठी,नितिन लाहोटी, आकाश लाहोटी,मधुर सर्राफ,आयुष चांडक,सोमिल सर्राफ, कृष्णा लाहोटी सहित समाजजन व महिला व युवा वर्ग उपस्थित रहे।

समावेशी शिक्षा को लेकर शिक्षकों की संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न

सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के नामांकन, शैक्षणिक प्रगति और दिव्यांग मूल्यांकन शिविर की तैयारियों पर हुई चर्चा

सुसनेर/ गिरिराज बंजारिया/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले (सीडब्ल्यूएसएन) बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन शिक्षा केंद्र देहरिया सोयत एवं जन शिक्षा केंद्र सोयत की संयुक्त समीक्षा बैठक सांदीपनि विद्यालय सोयतकला में तथा जन शिक्षा केंद्र डोंगरगांव की बैठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगांव में आयोजित की गई। बैठक का संचालन एमआरसी ओमप्रकाश पाटीदार ने किया। विकासखंड स्त्रोत समन्वयक राधेश्याम पाटीदार के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के नामांकन, नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक प्रगति तथा समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों ने बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सहायक उपकरणों तथा व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

एमआरसी ओमप्रकाश पाटीदार ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण गतिविधियों का संचालन किया जाए तथा अभिभावकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाए। उन्होंने छात्रवृत्ति, शासकीय योजनाओं एवं अन्य लाभकारी सुविधाओं का लाभ पात्र बच्चों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर भी विशेष बल दिया।

बैठक में बताया गया कि 24 जून 2026 को जनपद पंचायत सुसनेर में दिव्यांगजन मूल्यांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड तथा सहायक उपकरणों के लिए आवश्यक मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों से पात्र बच्चों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की गई।

बैठक में बीएससी मुकेश पालीवाल, जनशिक्षक भेरूसिंह सिसोदिया, रामदयाल गुर्जर, इफ्तियार खान, मनीष शर्मा सहित अन्य शिक्षक एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में विद्यालय परिसरों को दिव्यांगजन-अनुकूल बनाने, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनकी शिक्षा की गुणवत्ता एवं सर्वांगीण विकास के लिए सभी संबंधित पक्षों द्वारा सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया गया।

बड़ावदा पुलिस का सराहनीय नवाचारः सीपीआर प्रशिक्षण देकर बताए हार्ट अटैक से बचाव के तरीके

बड़ावदा/प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आमजन की सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ावदा पुलिस द्वारा सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को देखते हुए पुलिसकर्मी स्वयं चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को आपात स्थिति में जीवन बचाने के तरीके समझा रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अक्सर किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आने या हृदय गति रुकने की स्थिति में आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं और समय पर प्राथमिक उपचार नहीं दे पाते। ऐसी परिस्थितियों में सीपीआर की सही जानकारी किसी व्यक्ति का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

जागरूकता अभियान के दौरान सब इंस्पेक्टर मोहनलाल बडोदिया ने लोगों को सीपीआर देने की विधि समझाते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आए या वह बेहोश होकर सांस लेना बंद कर दे, तो तत्काल सीपीआर शुरू करना चाहिए। समय रहते दिया गया सीपीआर मरीज की जान बचाने में अत्यंत प्रभावी साबित हो सकता है।

वहीं एएसआई शिवजी यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं, सार्वजनिक स्थलों अथवा अन्य आपात परिस्थितियों में यदि प्रशिक्षित व्यक्ति समय पर सहायता प्रदान करे तो कई अनमोल जीवन बचाए जा सकते हैं। इसी उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो भविष्य में भी आमजन के हित में निरंतर जारी रहेगा।

अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं मेडिकल कर्मचारियों ने उपस्थित लोगों को सीपीआर की व्यवहारिक जानकारी भी दी तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले आवश्यक कदमों से अवगत कराया।

श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट करेगा समाजसेवी डॉक्टर गेहलोत का सम्मान

अकोदिया/ अमर सिंह मेवाडा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अकोदिया श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट शाजापुर जिला अध्यक्ष समाजसेवी डॉक्टर सुशील कुमार जी गेहलोत को प्रोग्रेसिव पेंशनर संगठन अकोदिया ब्लॉक इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने पर श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट अकोदिया एवं महिला इकाई अकोदिया द्वारा बुधवार शाम 5:00 बजे स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है नगर मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि यह आयोजन बुधवार शाम 5:00 बजे होटल सांवरिया में आयोजित होगा शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर महिला मंडल नगर अध्यक्ष वर्षा कुशवाह के धार्मिक यात्रा से वापसी होने पर ट्रस्ट की ओर से स्वागत सम्मान किया जाएगा कार्यक्रम में अतिथि के रूप में ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल महिला मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष रचना शर्मा जिला अध्यक्ष बिंदु सोनी तहसील अध्यक्ष रेखा खत्री समाज सेवीका मीनाक्षी चौरासिया सहित ट्रस्ट के सभी सदस्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट अकोदिया ने सभी श्याम प्रेमियों से आयोजन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी को ज्ञापन देकर वार्ड 10 में आरसीसी सड़क व पक्की नाली निर्माण की मांग

सुसनेर/ गिरिराज बंजारिया/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार को नगर के वार्ड क्रमांक 10 के रहवासियों ने नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद वाली गली में आरसीसी सड़क एवं पक्की नाली निर्माण की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि यह मार्ग डाक बंगला रोड को मैना रोड से जोड़ता है तथा हरिजन मोहल्ला, बाडपीड़ित कॉलोनी, बाबा रामदेवजी की बाड़ी सहित आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों का मुख्य आवागमन इसी रास्ते से होता है। रहवासियों ने बताया कि गली की सड़क वर्षों पुरानी और पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह-जगह गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। गर्मी के दिनों में धूल उड़ती रहती है, जबकि बारिश के समय पूरी गली में कीचड़ और जलभराव की स्थिति बन जाती है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि गली की नालियां कच्ची होने के कारण उनकी नियमित सफाई नहीं हो पाती। इससे गंदा पानी जमा रहता है जिससे मच्छर-मक्खियों का प्रकोप बढ़ने के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। इस समस्या से मोहल्लेवासियों के अलावा राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। रहवासियों ने नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए वार्ड क्रमांक 10 की मस्जिद वाली गली में शीघ्र आरसीसी सड़क एवं पक्की नालियों का निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को धूल, कीचड़ और जलभराव जैसी समस्याओं से स्थायी राहत मिल सके। इस दौरान वार्डवासियों ने शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई।

बड़वानी में सात दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण का तीसरा सत्र प्रारंभ

बडवानी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), मुख्यालय म.प्र. होमगार्ड्स के आदेशों, कलेक्टर जिला बड़वानी श्रीमती जयति सिंह के निर्देशन तथा संभागीय सेनानी इंदौर श्रीमती प्रीति बाला सिंह के मार्गदर्शन में सात दिवसीय श्युवा आपदा मित्र प्रशिक्षणश् (तृतीय सत्र) का शुभारंभ किया गया। इस सत्र में जिले के 231 युवा आपदा मित्र कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रथम दिन मुख्य अतिथि संभागीय सेनानी श्रीमती प्रीति बाला सिंह द्वारा माँ सरस्वती के पूजन के साथ प्रशिक्षण का विधिवत आरंभ किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने आपदा मित्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वर्तमान वर्षा ऋतु में जिला प्रशासन को संभावित बाढ़ आपदा एवं राहत कार्यों में सहयोग देने के साथ-साथ इन युवाओं को आगामी सिंहस्थ कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के लिए भी तैयार होना है।

सकलेचा के नेतृत्व मे यात्री विकास एव सुझाव मंच का नवीन गठन

नितिन जैन अध्यक्ष रवि चोहान सचिव बने

नागदा/ राजेश सकलेचा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। यात्री सुविधाओं के विकास एवं जनहित कार्यों को गति देने के उद्देश्य से वरिष्ठ समाजसेवी राजेश सकलेचा के नेतृत्व में यात्री विकास एवं सुझाव मंच की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।

सर्वसम्मति से नितिन जैन (उन्हेल वाले) को अध्यक्ष, रवि चौहान (पिपलोदा बागला वाले) को सचिव तथा दीपक जैन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं गौतम लश्करी, जीवनलाल जैन, दिनेश सेठिया और प्रकाश मालपानी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

बैठक में मंच के नए संकल्प आपका सुझाव, हमारा संकल्प के साथ यात्रियों की समस्याओं के समाधान, सुविधाओं के विस्तार और जनहित के मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। राजेश सकलेचा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को जनसेवा के कार्यों में सक्रिय रहने का आह्वान किया।

इन्होने दी बधाई - अनिल शर्मा विनायक, दुर्गेश राठोड, डा0 चंदनारायण शुक्ला, हिमांशु वासु ओझा, निलेश जैन सोलकी, राजेन्द्रकुमार जैन,निर्मल जैन, मनोज गांग, धर्मेन्द्र बम, मनीष चपलोत, प्रमोद कोठारी, ओमप्रकाश शर्मा, आतु बाबा, संदीप धावरे, राजकुमार जैन, हेमन्त कोठारी, जितेन्द्र खेमसरा, प्रदीप जैन, मनोज सोनी, अभिषेक अग्रवाल, शरद जैन,सुनिल सकलेचा, अनुज नाहर, अमित बम, मनीष भंडारी, अरविन्द नाहर,दिपक गांग, श्रेणीक बम,शेलेन्द्र कोठारी, गिरधारी लाल सोनी, निर्मल जेन, दिलीप काठेड, हेमन्त कांकरिया, हर्षित नागदा, सुनिल जेन, राकेश चोहान।

अग्निवीर में चयनित हुए विनोद परमार, समाजजनों ने किया भव्य स्वागत

बड़ावदा/ प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के युवा विनोद परमार का भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के अंतर्गत चयन होने पर समाजजनों एवं नगरवासियों में हर्ष का माहौल रहा। इस अवसर पर विनोद परमार का पुष्पमालाओं से स्वागत कर ढोल-धमाकों के साथ नगर में जुलूस निकाला गया तथा उन्हें प्रशिक्षण के लिए रवाना होने पर शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान समाजजनों ने विनोद परमार का सम्मान करते हुए उनकी उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। नगर में निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन, मित्र एवं परिजन शामिल हुए और देश सेवा के लिए चयनित होने पर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विनोद परमार ने कहा कि उनका चयन कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि यदि लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन हो तो कोई भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। नगरवासियों ने विनोद परमार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें प्रशिक्षण एवं देश सेवा के लिए शुभकामनाएं दीं।

पहली झमाझम बारिश से सुसनेर तरबतर, कई इलाकों में जलभराव, मेना रोड पर घर में घुसा पानी

सूचना मिलते ही बारिश में मौके पर पहुंचे नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी, कर्मचारियों ने नाले का जाम हटाकर कराई पानी की निकासी

सुसनेर/ गिरिराज बंजारिया/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार दोपहर नगर में मानसून की पहली जोरदार बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक गरज-चमक के साथ हुई झमाझम बारिश ने पूरे नगर को तरबतर कर दिया। लंबे समय से उमस भरी गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को मौसम के बदलते मिजाज ने बड़ी राहत दी। बारिश के बाद दिनभर मौसम सुहावना बना रहा और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि पहली ही तेज बारिश में नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खुल गई। कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान नरबदिया क्षेत्र में नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और कई स्थानों पर नालों के ऊपर से पानी बहने लगा। इससे आसपास की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। राहगीरों और वाहन चालकों को पानी से भरी सड़कों से होकर गुजरना पड़ा। कई स्थानों पर लोगों को अपने घरों और दुकानों के सामने जमा पानी निकालने की मशक्कत करनी पड़ी। सबसे अधिक परेशानी मेना रोड क्षेत्र में देखने को मिली। यहां स्थित नाले में कचरा एवं सीमेंट की पटि का एक टुकड़ा फंस जाने से नाला पूरी तरह जाम हो गया। पानी की निकासी बंद होने के कारण बारिश का पानी तेजी से एक मकान में घुस गया जिससे परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी सूचना तत्काल नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी को दी गई।

सूचना मिलते ही अध्यक्ष प्रदीप सोनी बारिश के बीच ही नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का निरीक्षण कर तत्काल नाले की सफाई शुरू करवाई। सफाई कर्मचारियों ने नाले में फंसी पटिया और कचरे को हटाकर पानी की निकासी सुचारु कराई। कुछ ही देर में जमा पानी निकलना शुरू हो गया और प्रभावित परिवार को राहत मिली। स्थानीय नागरिकों ने त्वरित कार्रवाई के लिए नगर परिषद की टीम का आभार भी व्यक्त किया। नगरवासियों का कहना है कि मानसून की शुरुआत में ही हुई इस बारिश ने यह संकेत दे दिया है कि बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। लोगों ने मांग की कि नगर के सभी प्रमुख नालों की समय-समय पर सफाई कराई जाए ताकि आगामी दिनों में भारी बारिश के दौरान जलभराव और घरों में पानी घुसने जैसी समस्याओं से बचा जा सके। पहली बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया, वहीं नगर परिषद के लिए जल निकासी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की चुनौती भी सामने रख दी।

डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदानए त्याग और राष्ट्रवाद से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है. अर्चना चिटनिस

बलिदान दिवस पर प्रतिमा पर माल्यार्पण, प्रतिमा जीर्णोद्धार, उद्यान विकास एवं भव्य प्रवेश द्वार निर्माण के दिए निर्देश

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जनसंघ के संस्थापकए प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी ,भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ.मनोज माने, नेपानगर विधायक सुश्री मंजू दादू, महापौर श्रीमती माधुरी पटेल ने जिला नेत्र चिकित्सालय परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, समर्पण और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जो संघर्ष कियाए वह आने वाली पीढियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। डॉ.मुखर्जी के आदर्श आज भी हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदैव राष्ट्रीय एकता को अपना प्रथम लक्ष्य माना। कश्मीर में ष्एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगेष् के उनके संकल्प ने देश की राजनीति को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35.ए को हटाकर उनके सपनों को साकार करने का कार्य किया गया है, जो उनके बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

श्रीमती चिटनिस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंची ह, उसके पीछे हमारे पितृ पुरुषों का त्यागए तपस्या और राष्ट्र के प्रति समर्पण है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।

इस अवसर पर श्रीमती चिटनिस ने चिकित्सालय परिसर स्थित डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिमा परिसर में आकर्षक उद्यान विकसित करने तथा लालबाग मार्ग से जिला नेत्र चिकित्सालय तक पहुंचने के लिए भव्य प्रवेश द्वार निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यह परिसर राष्ट्रवादी विचारों और जनसेवा की प्रेरणा का केंद्र हैए इसलिए इसके समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर में जिला नेत्र चिकित्सालय की स्थापना एवं उसके विकास में श्रीमती अर्चना चिटनिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके सतत प्रयासों से जिले को विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा सेवाओं की सौगात मिली। उनके कार्यकाल में वर्ष 2008 से 2013 के दौरान लगभग 48 लाख रुपये की लागत से जिला नेत्र चिकित्सालय का उन्नयन कराया गया। साथ ही लगभग 59 लाख रुपये की लागत से इसी परिसर में ब्लड बैंक की स्थापना कर स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान की गई। उनके प्रयासों से विशेष नेत्र चिकित्सा शिविरों एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन अभियानों का नियमित संचालन हुआए जिससे हजारों मरीजों को लाभ मिला।

कार्यक्रम के उपरांत श्रीमती चिटनिस ने जिला नेत्र चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल में चल रहे सुधार एवं उन्नयन कार्यों की समीक्षा की। उनके निर्देशानुसार अस्पताल में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने, आर.ओ.वाटर कूलर स्थापना,भवन मरम्मत, रंग.रोगन, प्लंबिंग, फर्नीचर व्यवस्था तथा ऑपरेशन थिएटर के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सहित विभिन्न कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय.सीमा में पूर्ण करने तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज जी माने ने कहा कि स्व. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और जम्मू.कश्मीर को भारत में पूरी तरह मिलाने के प्रखर समर्थक थे। वे अनुच्छेद 370 के घोर विरोधी थे,वे इस व्यवस्था का विरोध करने के लिए 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू.कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े,वहां पहुंचते ही उन्हें राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया गया। हिरासत में रहने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और 23 जून 1953 को संदेहास्पद परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। इस दौरान कश्मीर और बंगाल को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई।

उपरोक्त जानकारी देते हुवे भाजपा जिला मिडिया प्रभारी मुकेश पुर्वे ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री सर्वश्री चिंतामन महाजन, ईश्वर चौहान, संजय जाधव,किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री मनोज लधवे, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलिप श्रॉफ ,महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सावीत्री बत्रा, पिछडा मोर्चा जिलाध्यक्ष राजु पाटील,पूर्व महापौर अनिल भोसले सहित भाजपा नेता नरहरी दिक्षित, कैलाश पारीक,प्रशांत पाटील, रवि गावडे, सुनिल वाद्ये, प्रदीप कसेरा, प्रशांत लाड,प्रभाकर चौधरी, किशोर शाह, मनोज टंडन, दिनकर पाटील, किरन रायकवार, सुधा चौकसे, ममता दुबे,रीना महाजन,भरत रावल,संभाजी सगरे, रूद्रेश्वर एन्डोले, मंडल अध्यक्ष सर्वश्री रविन्द्र काकडे,अमोल भगत, किशोर राठौर, राजकुमार वाद्य, धनराज महाजन,आशिष शुक्ला,राजा इंगले, मनोज फलवानी, नितेश दलाल, राजेश महाजन, अशोक राठौर, विजय राठौर, निलेश सोनी, प्रसाद उमाले सहित भाजपा जनप्रतिनिधी,संगठन पदाधिकारी,प्रकोष्ठो,मोर्चा, पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्तागण उपस्थित थे।

नगर में संत के आगमन से समाज सहित नगर वासी प्रफुल्लित हुए

उन्हेल/ निर्मल आर सोलंकी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उन्हेल नगर में जैन श्रुत संवेगी आदित्य सागर मुनि जी के अल्प समय प्रवास पर मीडिया से चर्चा में कुछ खट्टी मीठी बातें की जिसमें प्रमुख रूप से सोशल मीडिया का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है परंतु मुनि जी ने सदुपयोग करना उसे सत्कर्म करना गाय को रोटी देना संतों की आओ भगत कर उनको अन्य दान देना युवाओं को संभल संभल कर चलने की बात मीडिया के माध्यम से नवयुवक तक पहुंचने की बात कही संत त्याग तपस्या का दूसरा नाम है हम गाड़ी का उपयोग इसीलिए नहीं करते की उससे हिंसा होती है और जीव जंतु के मरना के आशंका के कारण हम बिहार पर पैदल निकलते हैं जितना चलना होता है उतना चलकर एक समय भोजन कर फिर अपने अगले स्थान को विश्राम के लिए जाते हैं यही मुनियों की दिनचर्या होती है नीचे जमीन है ऊपर आसमान है 40 से 50000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ली है मुनिजी ने उदयपुर चौमासा करने की बात कहीं 4 महीने एक जगह रहकर तपस्या करना चौमासा कहलाता है।

संजय चौक स्थित ट्रांसफॉर्मर में लगी आग, टला बड़ा हादसा

उन्हेल/ निर्मल आर सोलंकी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के सबसे व्यस्तम संजय चौक पर मंगलवार को उस समय भय का माहौल बन गया जब अचानक विद्युत डीपी (ट्रांसफॉर्मर) में आग लग गई। व्यस्त चौराहा होने के कारण वहां लोगों की काफी आवाजाही रहती है, जिससे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। गनीमत रही कि स्थानीय रहवासियों ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए विद्युत विभाग को सूचित किया। विभाग के कर्मचारियों ने समय रहते बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यदि आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जाता, तो पास में स्थित कई गुमटियाँ इसकी चपेट में आ सकती थीं। स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से आग बुझाई गई।आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया हैं प्रथम दृष्टियां शॉर्ट सर्किट से आग लगा माना जा रहा हैं रहवासियों ने विद्युत विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने की मांग की है।

1 जुलाई को जिला स्तरीय युवा संगम का आयोजन

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में मध्यप्रदेश शासन की रोजगारोन्मुखी नीति के अंतर्गत जिले के युवाओं को रोजगार, स्व-रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तरीय युवा संगम का आयोजन 01 जुलाई 2026 (बुधवार) को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासकीय शहीद चन्द्रशेखर आजाद महाविद्यालय, झाबुआ में किया जाएगा। युवा संगम में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की लगभग 5 से 7 कंपनियां भाग लेंगी। कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा तथा रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल स्थापित कर शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी भी युवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना तथा मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। युवा संगम में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त की हो।

कलेक्टर ने छात्रावास व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश

झाबुआ/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में जिले के जनजातीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा केन्द्र अंतर्गत संचालित छात्रावासों की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त छात्रावास वार्डनों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों ने सहभागिता की।

बैठक में कलेक्टर ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी सीट रिक्त न रहे। उन्होंने कहा कि छात्रावास केवल आवासीय सुविधा का केंद्र न होकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम बनें। इसके लिए छात्रावासों में अनुशासन, सुरक्षा, शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी छात्रावास वार्डन छात्रावास परिसर में नियमित रूप से निवास करें तथा चौकीदारों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक आवश्यकताओं की सतत निगरानी की जाए।

उन्होंने कहा कि छात्रावासों में पेयजल, स्वच्छता, विद्युत, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं गुणवत्तापूर्वक उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में कलेक्टर ने छात्रावासों में प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाए।

एसपी राजेश व्यास ने सुनीं 64 फरियादियों की समस्याएं, सीएम हेल्पलाइन की 15 शिकायतों का मौके पर निराकरण

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन के निर्देशानुसार मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम नीमच में जिला स्तरीय जनसुनवाई, शिकायत निवारण एवं सीएम हेल्पलाइन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने की। इस दौरान आमजन की शिकायतें सुनने के साथ-साथ लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया।

शिविर में जिलेभर से पहुंचे फरियादियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और शिकायतें पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के समक्ष रखीं। एसपी ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के दौरान सीएम हेल्पलाइन की लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 की कुल 15 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर उन्हें बंद कराया गया। वहीं जिला स्तरीय जनसुनवाई में लगभग 64 फरियादियों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याएं रखीं, जिनके शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई से संबंधित शिकायतें, सामाजिक सुरक्षा और अन्य संवेदनशील मामलों में विशेष गंभीरता बरती जाए तथा आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

एसपी व्यास ने यह भी निर्देश दिए कि थाना स्तर पर समय-समय पर जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सके और पुलिस-जन संवाद को मजबूत बनाया जा सके।

जिला स्तरीय सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत निवारण शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, एसडीओपी जावद रोहित राठौर, एसडीओपी मनासा शाबेरा मंसूरी, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक कारूलाल जाट, अजाक थाना प्रभारी निरीक्षक शब्बी मेव सहित विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।

शिविर के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण और बेहतर पुलिस व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

अर्चना चिटनिस के सतत प्रयासों एवं किसानों की अथक मेहनत से बुरहानपुर के केले को मिला जीआई टैग, दुनिया में बनेगी विशिष्ट पहचान

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बुरहानपुर जिले के लिए यह ऐतिहासिक गौरव और उपलब्धि का क्षण है कि जिले के प्रसिद्ध केले को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है। इससे बुरहानपुर का केला अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। यह सफलता किसानों की अथक मेहनत विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) के दीर्घकालिक एवं सतत प्रयासों का परिणाम है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती अर्चना चिटनिस ने जिले के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि बुरहानपुर का केला यहां की कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत और क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों का प्रतीक है। जीआई टैग मिलने से इसकी विशिष्टता को आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य, व्यापक बाजार और निर्यात के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

श्रीमती चिटनिस ने बताया कि बुरहानपुर के केले को जीआई टैग दिलाने की पहल वर्ष 2013-14 में उनके कार्यकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी। उस समय जिले के केले की विशिष्टता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने तथा किसानों को इसका वास्तविक लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस विषय को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया। इसके बाद लगातार विभिन्न विभागों, कृषि एवं उद्यानिकी विशेषज्ञों तथा संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक से अधिक समय तक चले निरंतर प्रयास, तकनीकी दस्तावेजीकरण, शोध एवं विभागीय समन्वय के परिणामस्वरूप आज बुरहानपुर के केले को यह प्रतिष्ठित पहचान प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि केवल एक उत्पाद को मिला सम्मान नहीं है, बल्कि जिले के हजारों किसानों के परिश्रम, समर्पण और कृषि उत्कृष्टता का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ सम्मान है।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि मध्यप्रदेश में विशिष्ट कृषि एवं पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की दिशा में लगातार कार्य किया गया है। बालाघाट जिले के प्रसिद्ध चिन्नौर धान को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जिससे उसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली। इसके साथ ही महेश्वर की विश्वविख्यात महेश्वरी साड़ी तथा हरदा क्षेत्र के बांस उत्पाद भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुके हैं। अब बुरहानपुर का केला भी प्रदेश के गौरवशाली जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की सूची में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ''वोकल फोर लोकल'' तथा ''लोकल टू ग्लोबल'' विजन है तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बुरहानपुर के केले को मिला जीआई टैग इसी सोच और किसान हितैषी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है।

श्रीमती चिटनिस ने कहा कि जीआई टैग मिलने के बाद बुरहानपुर का केला दुनिया के बाजारों में अपनी अलग पहचान बनाएगा। इससे जिले के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी तथा बुरहानपुर का नाम गुणवत्तापूर्ण केले के उत्पादन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों और केला प्रसंस्करण इकाइयों को भी नई गति मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में हजारों किसान केले की खेती से जुड़े हुए हैं और बड़ी मात्रा में उत्पादन कर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जीआई टैग मिलने से किसानों को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक सशक्त होगी।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने जिले के किसानों, उद्यानिकी विभाग, प्रशासन एवं इस प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों, दृढ़ संकल्प और बुरहानपुर की मिट्टी से जुड़े किसानों की मेहनत का गौरवपूर्ण परिणाम है। बुरहानपुर के केले को मिला जीआई टैग आने वाले वर्षों में जिले की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और किसानों की समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।

शासकीय कार्य में बाधा एवं कर्मचारियों को धमकाने वाले फरार आरोपी को नेपानगर पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री आशुतोष बागरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शेण्डे एवं एसडीओपी नेपानगर श्री निर्भय के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नेपानगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना नेपानगर के अपराध क्रमांक 210/2026 धारा 296, 132, 351 भारतीय न्याय संहिता के प्रकरण में घटना दिनांक से फरार चल रहे आरोपी कालाम पिता सलीम मुल्तानी निवासी नयाखेड़ा को पुलिस टीम द्वारा महाराष्ट्र के एदलाबाद से हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

आरोपी द्वारा एमपीईवी के कर्मचारियों के साथ अभद्र एवं अश्लील गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकाया गया था तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। उक्त घटना के संबंध में थाना नेपानगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।

प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। तलाश के दौरान आरोपी के महाराष्ट्र राज्य के एदलाबाद क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया और विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई।

सराहनीय भूमिका:- चौकी प्रभारी नावरा उप निरीक्षक श्री अजय सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक सुभाष मोरे एवं प्रधान आरक्षक मुकेश मोरे की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

बुरहानपुर में महिला सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मार्गदर्शन एवं नगर निगम बुरहानपुर के सहयोग से फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा महिला सफाई मित्रों हेतु स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन परमानंद गोविंदवाला ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यशाला का उद्देश्य महिला सफाई मित्रों को सफाई कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों, स्वच्छता आदतों तथा सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ।

अपने संबोधन में असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि महिला सफाई मित्र शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों का स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों का नियमित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण सत्र में प्रतिभागियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, कचरे के सुरक्षित संग्रहण एवं परिवहन, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सुरक्षा उपकरणों—जैसे ग्लव्स, मास्क, गमबूट एवं एप्रन—के सही उपयोग और रखरखाव की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यशाला के समापन अवसर पर असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान महिला सफाई मित्रों ने सक्रिय सहभागिता दिखाई और स्वास्थ्य व सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।

फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से टीम ने प्रशिक्षण एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पहल महिला सफाई मित्रों को अधिक सुरक्षित, जागरूक और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की राज्य स्तरीय रैंकिंग में झाबुआ ने हासिल किया प्रथम स्थान

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। किसान कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सतत मॉनिटरिंग के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड पर जारी नवीनतम जिलावार रैंकिंग में झाबुआ जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मई 2026 माह में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग से संबंधित विभिन्न की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। इन विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन कर जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा जिलों द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की गई प्रगति एवं विभागाध्यक्षों द्वारा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर मध्यप्रदेश स्टेट एजेंसी फॉर पब्लिक सर्विसेस, भोपाल द्वारा 16 जून 2026 को माह अप्रैल एवं मई 2026 की जिलावार रैंकिंग जारी की गई।

जारी रैंकिंग के अनुसार माह अप्रैल 2026 में झाबुआ जिले ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जबकि माह मई 2026 में झाबुआ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। मई माह की रैंकिंग में झाबुआ प्रथम, मंदसौर द्वितीय तथा बालाघाट तृतीय स्थान पर रहा।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

चरक अस्पताल की लिफ्ट कंपनी का ठेका होगा समाप्त

देर रात कलेक्टर ने औचक निरीक्षण में जताई नाराजगी- नई एजेंसी के लिए टेंडर के निर्देश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला चिकित्सालय चरक भवन में ठेकेदार द्वारा लंबे समय से लिफ्टों के खराब रखरखाव और संचालन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कल देर रात कलेक्टर यहां औचक निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने लिफ्ट संचालन एवं रखरखाव में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कंपनी को टर्मिनेट करने और नई कंपनी के चयन के लिए तत्काल टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

कल रात 12 बजे के लगभग कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यहां अव्यवस्थाएं देख स्पष्ट कहा कि मरीजों की सुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।यह दौरान उनके साथ सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट भी थे। सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। यहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से जानकारी लेने के साथ ड्यूटी चार्ट की जांच की गई। उन्होंने अस्पताल स्टाफ को अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म पहनने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल की ड्रेनेज व्यवस्था में मौजूद समस्याओं पर भी चिंता जताई गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बर्थ वेटिंग वार्ड और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड का निरीक्षण कर इनका नियमित उपयोग करने को कहा। कलेक्टर ने लेबर रूम, प्रतीक्षालय और पुरुष मेडिकल वार्ड का भी दौरा किया। अस्पताल के मुख्य मार्ग और प्रवेश द्वार पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने तथा सभी मंजिलों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन से सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सहयोग और उपचार पद्धतियों का भी उपयोग करने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार पटेल, सिविल सर्जन डॉ. संगीता पलसानिया, आरएमओ डॉ. चिन्मय चिंचोलीकर एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे।

वर्षा के दौरान निर्माण स्थलों पर सुरक्षा, जल निकासी एवं यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें – संभागायुक्त श्री सिंह

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सिंहस्थ 2028 के तहत विभिन्न अधोसंरचना के विकास कार्य निर्माणाधीन हैं। विकास कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करते हुए सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं संभागायुक्त श्री आशीष सिंह तथा जिला कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिंहस्थ 2028 के तहत शहर में प्रचलित निर्माण कार्यों की तैयारियों के अंतर्गत नगर निगम, उज्जैन विकास प्राधिकरण एवं उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। संभागायुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि वर्षा के दौरान निर्माण स्थलों पर सुरक्षा, जल निकासी एवं यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए।

सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए शहर में संचालित सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, ड्रेनेज, पेयजल तथा अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह ने सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं तथा कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।

28 जून को 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 जून रविवार को किया जाएगा। अभियान के तहत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए दो बूंद जीवनरक्षक दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए पूरे जिले में पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल ने बताया कि अभियान के दौरान कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 28 जून को बूथों पर दवा पिलाने के बाद छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर पोलियो की खुराक देंगी। अभियान में ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, झुग्गी-झोपड़ियों और घुमक्कड़ आबादी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दो बूंद दवा अवश्य पिलाएं, ताकि पोलियो मुक्त भारत का संकल्प मजबूत बना रहे।

उज्ज्वला योजना से भारती के जीवन में आया सकारात्मक परिवर्तन

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाली जिले की कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। इसी क्रम में उज्जैन निवासी श्रीमती भारती प्रजापत ने योजना के लाभों को साझा करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। श्रीमती भारती प्रजापत ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें एलपीजी कनेक्शन मिलने से पहले वे लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकाती थीं। चूल्हे से निकलने वाले धुएं के कारण उन्हें सांस संबंधी अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था तथा घर का वातावरण भी प्रदूषित रहता था। गैस कनेक्शन मिलने के बाद उनके जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। अब स्वच्छ ईंधन के उपयोग से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, घर का वातावरण स्वच्छ रहता है और भोजन पकाने में भी सुविधा तथा समय की बचत हो रही है।

काल भैरव मंदिर के सामने दुकानों में लगी आग

तड़के लगी आग ने खोली सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल, अगर दर्शन के समय होता हादसा तो भगदड़ में जा सकती थीं कई जानें

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। काल भैरव मंदिर के ठीक सामने मंगलवार तड़के लगी भीषण आग ने न केवल चार पूजन सामग्री की दुकानों को राख में बदल दिया, बल्कि शहर की फायर सेफ्टी व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह करीब 5 बजे लगी आग ने कुछ ही मिनटों में चार दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि उसे काबू करने के लिए दमकल विभाग की पांच गाड़ियों को लगभग एक घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।

स्थानीय लोगों के अनुसार आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं और दुकानों में रखी पूजन सामग्री, प्लास्टिक के सामान, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री ने आग को और भड़का दिया। देखते ही देखते चारों दुकानें धू-धू कर जलने लगीं। लोगों का यह भी कहना था कि तड़के भीड़ नहीं थी, अगर यही हादसा कुछ घंटे बाद होता तो कई लोगों की जानें जा सकती थी।

फायर सेफ्टी इंतजाम कहां थे- हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मंदिर क्षेत्र जैसे अति संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके में संचालित दुकानों में आखिर फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकानों में न तो अग्निशामक यंत्र दिखाई दिए और न ही किसी प्रकार की आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखी जाती है, वहां अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। इसके बावजूद काल भैरव मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के सामने सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है।

अगर एक-दो घंटे बाद लगती आग तो हो जाता बड़ा हादसा- मंगलवार को आग तड़के उस समय लगी, जब मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू नहीं हुई थी। लेकिन यदि यही आग सुबह दर्शन के व्यस्त समय में लगती, तो हालात बेहद भयावह हो सकते थे।

प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर और आसपास की दुकानों में मौजूद रहते हैं। ऐसे में आग की लपटें और धुआं फैलने के साथ भगदड़ की स्थिति बन सकती थी। जानकारों का कहना है कि कई बार आग से ज्यादा मौतें भगदड़ और अफरा-तफरी के कारण होती हैं। संकरी सड़क, दुकानों की कतार और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बड़ा जनहानि वाला हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

नगर निगम के अनुमति और फायर विभाग पर उठे सवाल- घटना के बाद नगर निगम के फायर सेफ्टी विभाग और अनुमति शाखा की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। यदि दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई थी तो क्या फायर सेफ्टी मानकों की जांच की गई थी? क्या नियमित निरीक्षण हुए थे? क्या दुकानदारों को अग्निशमन उपकरण रखने के निर्देश दिए गए थे? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं हैं। शहर में पहले भी कई बार फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनियां और अभियान चलाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर नजर नहीं आता। काल भैरव मंदिर के सामने हुई यह घटना प्रशासनिक दावों और वास्तविक व्यवस्थाओं के बीच की खाई को उजागर करती है।

लोगों ने बचाने की कोशिश की, फिर पहुंची पांच दमकलें- आग लगते ही आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान आग की लपटें पास स्थित एक पेड़ तक पहुंच गई थीं, जिसे समय रहते बचा लिया गया।

कारणों की जांच जारी- फायर अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद साहू के अनुसार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार दुकानदारों को आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

सवाल जो जवाब मांगते हैं -मंदिर क्षेत्र की दुकानों में फायर सेफ्टी उपकरण क्यों नहीं थे?

-नगर निगम और फायर विभाग ने आखिरी बार निरीक्षण कब किया था?

-अनुमति देते समय सुरक्षा मानकों की जांच हुई थी या नहीं?

-भीड़भाड़ वाले धार्मिक क्षेत्रों के लिए अलग सुरक्षा प्रोटोकॉल क्यों नहीं?

इस बार 5 लाख हेक्टेयर में होगी सोयाबीन की बोवनी

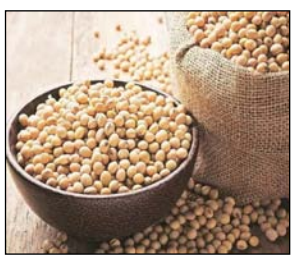

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। इंतजार के बाद जिले में हुई करीब साढ़े 3 इंच बारिश ने खरीफ सीजन की बोवनी का रास्ता खोल दिया है। मौसम की अनुकूलता के साथ किसानों ने खेतों की तैयारी तेज कर दी है और अब बोवनी का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 5.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य तय किया है, जिसमें सबसे अधिक करीब 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की जाएगी। यही वजह है कि ग्रामीण अंचलों में खेतों में ट्रैक्टरों की आवाजाही बढ़ गई है और खेती-किसानी की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

उल्लेखनीय है कि शनिवार और सोमवार को उज्जैन सहित जिले में जोरदार बारिश हुई थी जिसके बाद खेतों में पर्याप्त नमी बनने से किसान अंतिम जुताई, पाटा चलाने और बीजोपचार जैसे कार्यों में जुट गए हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार समय पर बोवनी और प्रमाणित बीजों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

किसान भी बेहतर उत्पादन और बाजार में अच्छे दाम की उम्मीद के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने लगे हैं। इस सीजन में किसानों के बीच सोयाबीन की उन्नत किस्में 9560, 2172, 2303 और 2434 सबसे अधिक पसंद की जा रही हैं। कृषि विभाग का कहना है कि ये किस्में बेहतर उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने के कारण किसानों की पहली पसंद बनी हुई हैं।

उज्जैन में नगर निगम इस साल 10 लाख पौधे लगाएगा

अगले वर्ष के लिए 15 लाख का लक्ष्य रखा गया - 2 साल में 25 लाख पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाएंगे

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में नगर निगम को इस साल 10 लाख पौधे लगाएगा और अगले वर्ष 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह सिंहस्थ से पहले आगामी दो वर्षों में 25 लाख पौधारोपण कर शहर को हरा भरा बनाया जाएगा।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के लिए नगर निगम और नगरीय प्रशासन विभाग संयुक्त रूप से बजट उपलब्ध कराएंगे। निगम के पास सडक़ चौड़ीकरण के दौरान पेड़ काटने के एवज में मिले 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा शासन स्तर से भी अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा। पौधारोपण के लिए शहर में खाली और अनुपयोगी जमीनों देख रहे हैं। नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों का सर्वे कर सूची तैयार की जा रही है। जून से मानसून के साथ ही पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस बार निगम केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी देखरेख और संरक्षण पर भी विशेष फोकस रहेगा। पौधारोपण का कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया जाएगा, जिसे पौधे लगाने के बाद दो वर्षों तक उनकी सुरक्षा, सिंचाई और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी विवि परिसर, तरणताल सहित 10 जगह चयनित की नगर निगम अपर आयुक्त संदीप शिवा के अनुसार प्रारंभिक चरण में विक्रम विश्वविद्यालय परिसर, तरणताल क्षेत्र, एमआर-5 रोड, चकोर पार्क सहित करीब 10 प्रमुख स्थलों का चयन किया है। इसके अलावा शहर के लगभग 400 उद्यानों में उपलब्ध खाली भूमि का उपयोग भी किया जाएगा। हर जोन में करीब 20 स्थानों को चिह्नित किया जाएगा, जिनमें सडक़ किनारे, चौरासी महादेव मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल व नदी किनारे आदि शामिल हैं।

स्व. पं. मोरेश्वर शास्त्री दीक्षित ने महाकवि कालिदास के जीवन पर खोज कर नया उदाहरण प्रस्तुत किया - विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा

महाकवि कालिदास की जन्मकुंडली बनाई थी पं. मोरेश्वर शास्त्री ने, शिप्रा तट पर था महाकवि का निवास - प्रो. शर्मा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पं. मोरेश्वर शास्त्री दीक्षित ने महाकवि कालिदास जी के जीवन पर खोज करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उक्त उद्गार उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पं. स्व. मोरेश्वर शास्त्री दीक्षित द्वारा प्रारम्भ किए गए महाकवि कालिदास जयंती समारोह में व्यक्त किए। यह समारोह त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित किया गया।

प्रमुख वक्ता के रूप में बोलते हुए सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलानुशासक प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि महाकवि कालिदास जयंती 22 जून को मनाने का श्रेय केवल स्व. पं. मोरेश्वर शास्त्री दीक्षित को जाता है। उन्होंने ही महाकवि कालिदास की जन्मतिथि का निर्धारण कर जन्मकुंडली बनाई थी। उन्होंने कहा कि कालिदास का निवास शिप्रा तट पर था। महाकवि कालिदास के काव्य में राष्ट्र की व्यापक अवधारणा निहित है। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति और परम्परा का निचोड़ हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. केदारनारायण जोशी ने कहा कि उज्जैन में महाकवि कालिदास पर प्रतिवर्ष दो आयोजन होते हैं, एक अखिल भारतीय कालिदास समारोह और दूसरा कालिदास जयंती समारोह।

छत के रास्ते दो दुकानों से चोरो ने उड़ाई हजारो की नगदी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मालीपुरा से लाल मजिस्द की ओर जाने वाले मार्ग पर रात में 2 दुकानों में चोरों ने धावा बोला। सुबह वारदात का पता चलाने पर पुलिस जांच के लिये पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे है। चोरों ने दुकानों से हजारों रूपये नगद चोरी किये है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोथरवाल टेलर्स और राजेश इलेक्ट्रिक शोरूम संचालक सोमवार सुबह दुकान पहुंचे और शटर खोला तो काउंटर पर सामान अस्त-व्यस्त दिखाई दिया। गल्ले खुले थे, जिसमें रखी नगद राशि गायब थी। दुकान में देखने पर पता चला कि चोरों ने छत के रास्ते धावा बोला था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस जांच के लिये मौके पर पहुंची। इस दौरान सामने आया कि इलेक्ट्रिक दुकान से करीब 50 हजार रूपये नगद और टेलर्स के यहां से 20 से 25 हजार रूपये नगद चोरी हुए है। कुछ कीमती सामान भी चोर ले गये थे। पुलिस ने चोरों का पता लगाने के लिये आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू किये है। फिलहाल सोमवार शाम तक दोनों दुकानदारों द्वारा मामले की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस जांच पूरी होते ही मामला दर्ज किया जायेगा। बताया जा रहा है कि चोरों की संख्या 2 से अधिक हो सकती है, रात में वह पास के मकान से चढ़कर दुकानों तक पहुंचे थे।

जमीन विवाद में दो पक्षो के बीच चले तलवार-डंडे

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मानसून की दस्तक के बाद खेतों में फसल बोने और अपने हिस्से की जमीन को लेकर विवाद के मामले सामने आने लगे हैं। ग्राम नवेली में दो पक्षों के बीच तलवार डंडे निकल आए। तीन लोग घायल हुए हैं।

भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नवेली में संतोष पिता नारायण धानक और सुनील पिता गोवर्धन सिंह आंजना के बीच आधा बीघा जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। जो न्यायालय में विचाराधीन भी है। शहर में दो दिन से हो रही बारिश के बाद संतोष खेत पर जमीन हांकने के लिए पहुंचा था उसी दौरान सुनील आंजना का परिवार भी मौके पर आ गया। दोनों पक्षों के बीच जमीन हांकने की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और तलवार डंडे निकल आए। विवाद में एक पक्ष से संतोष और अर्जुन घायल हुए हैं दूसरे पक्ष से सुनील आंजना को चोट लगी है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।

इधर भाइयों के बीच हुआ विवाद - खेत की जमीन को लेकर ग्राम मंगरोला में रहने वाले दो भाई संतोष पिता गजराज सिंह बेस और दिनेश बेस के बीच विवाद हो गया। दिनेश ने पत्थरों से हमला कर संतोष को घायल कर दिया। अस्पताल में भर्ती संतोष ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच सात बीघा जमीन थी एक बीघा जमीन बेचकर 6 बीघा जमीन का आधा-आधा बटवारा कर लिया गया था उसके पास तीन बीघा जमीन थी वह देवास रहने चला गया। सोमवार को वह अपनी जमीन पर खेती करने के लिए आया था इस दौरान भाई ने दूसरी जमीन पर खेती करने के लिए कहा और उसके हिस्से की जमीन भी देने की बात कही जिसको लेकर विवाद हुआ है।

तालोद में भी जमीन का झगड़ा- चिंतामण थाना क्षेत्र के ग्राम तालोद में इंदौर के रहने वाले रितेश पिता गोपाल पटेल और तलोद निवासी विजय पिता मोहन राठौर के बीच खेत की जमीन को लेकर विवाद हो गया। रितेश इंदौर से जमीन पर बोनी करने के लिए आया था। लेकिन विजय राठौर से उक्त जमीन का न्यायालय में विचाराधीन है। चिंतामण पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है

डबरी में नहाने उतरे दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। खेत के पास बनी शासकीय डबरी में मंगलवार शाम नहाने उतरे दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों के शव खोज कर बाहर निकले। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रलायता भोजा में शासकीय डबरी बनी हुई है। कुछ समय पहले ही डबरी का गहरी करंट किया गया था। करीब 30 फीट से ज्यादा गहरी डाबरी में मंगलवार शाम 4 के लगभग रितेश पिता भगवान बागरी 15 साल और उसका चचेरा भाई आयुष पिता भेरुलाल बागरी 11 साल निवासी रलायता भोजा अपने खेत से पास की डबरी पहुंचे और नहाने के लिए उतर गए। दोनों को गहराई का भान नहीं था और तैरना भी ठीक से नहीं आता था। बीच मे जाने पर दोनों सांस फूल गई और वह डूबने लगे। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें देखा तो शोर मचाया लेकिन दोनों गहराई में जा चुके थे। दोनों के परिवार को सूचना दी गई और गांव वालों को बुलाया गया। 1 घंटे की तलाश के बाद दोनों को बाहर निकल गया और अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। भेरूगढ़ थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर दोनों भाइयों देर शाम पोस्टमार्टम कराये। परिजनों ने बताया कि रितेश कक्षा आठवीं का छात्र था और आयुष कक्षा पांचवी में पढ़ता था। परिवार खेती किसानी के साथ मजदूरी का काम करता है।

चोरी के बाद 40 लाख के माल का कर लिया था बंटवारा

7 दिन बाद हिरासत में आया एक आरोपी, 2 की तलाश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। नागदा में प्रॉपर्टी डीलर के मकान में हुई 40 लाख की चोरी में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर आभूषण और नगद राशि का बंटवारा कर लिया था। विरासत में आरोपी के हिस्से की राशि और आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं दो साथियों की तलाश जारी है।

नागदा थाना पुलिस ने बताया कि सुनील नगर में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद आजाद मंसूरी के सूने मकान में 14-15 जून की रात चोरी की बड़ी वारदात हो गई थी अज्ञात बदमाश 40 लाख के आभूषण और नगदी चुरा कर ले गए थे। मामले में प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई थी और नागदा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से निकले हाईवे मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए थे। बाइक सवार तीन संदिग्ध दिखाई दिए जिनकी तलाश शुरू की गई। सप्ताहभर बाद चोरी में शामिल मुख्य आरोपी रतलामसिंह उर्फ रत्तु 26 वर्ष निवासी ग्राम सिगनुर, थाना गोगांवा, जिला खरगोन को सनावद से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने दो सहयोगियों दिपक सिकलीगर और शिवराज पिता हरपाल निवासीगण गंदवानी धार के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया है। नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी के अनुसार हिरासत में आए आरोपी की निशानदेही पर 6 लाख रुपए कीमत आभूषण और 70,000 रुपए नगद बरामद कर लिए गए हैं। चोरी के शेष आभूषण और नगदी फरार साथियों की गिरफ्त में आने पर बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम धार रवाना की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद आजाद की पत्नी और बच्चे अपने मायके गए हुए थे वहीं प्रॉपर्टी डीलर अपने कारोबार से संबंधित काम के चलते मंदसौर होते हुए राजस्थान गया था। जिसके चलते उसका मकान सुना था। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाकर ताला तोड़ चोरी को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी के अनुसार चोरी करने वाले बदमाश सिकलीगर हैं। जो दिन में रेकी करते हैं और रात में चोरी को अंजाम देते हैं उनके आपराधिक रिकार्ड भी तलाश किया जा रहे हैं।